RNI No. : DELBIL/2021/79984 ₹ 20

सीमा संघोष

जून 2023

अमेरिका में भारत की धाक

भारत अमेरिका में हुए रक्षा समझौते

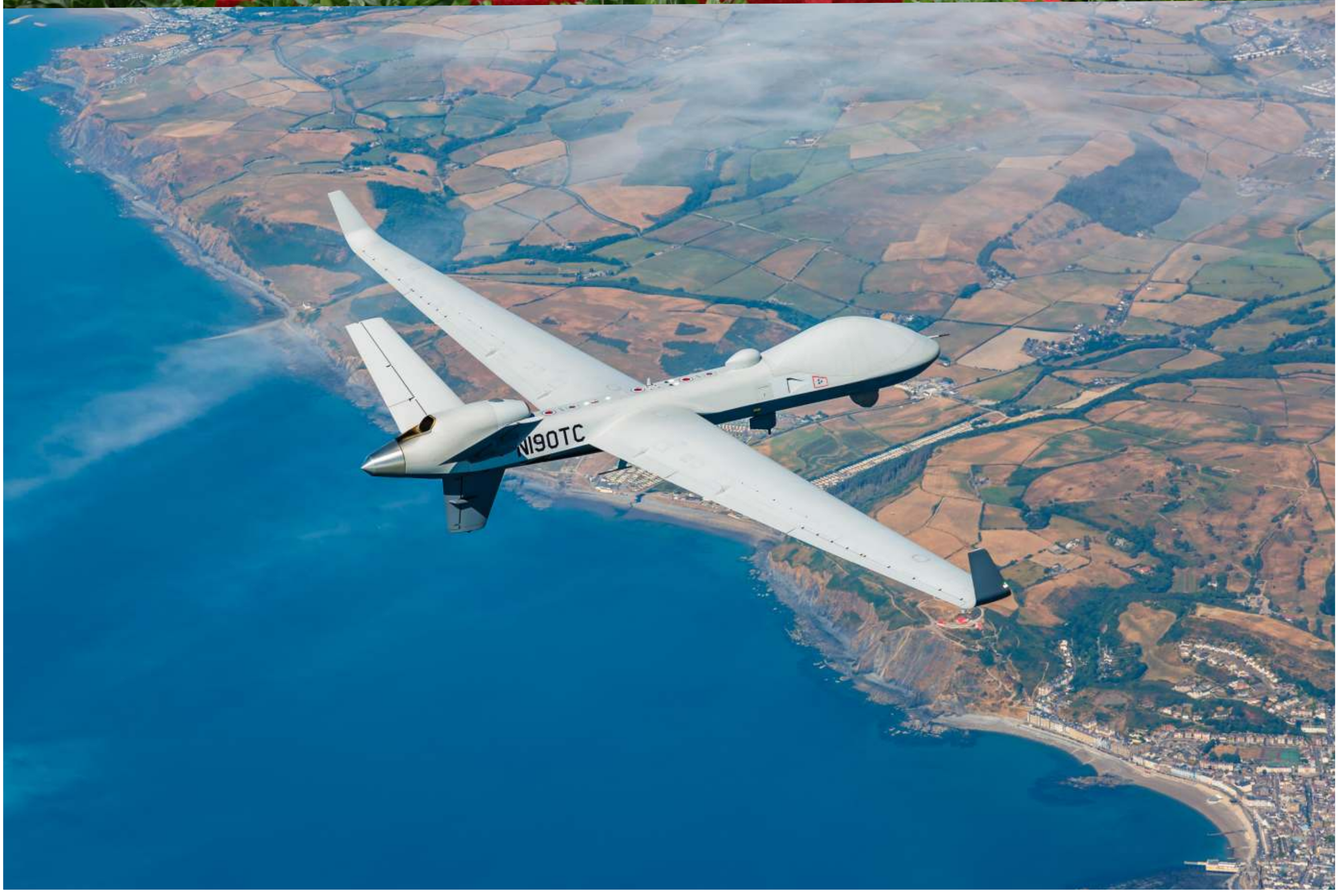
N190TC

संरक्षक - प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा
मुख्य सलाहकार - ब्रिगेडियर कपिल देव मल्होत्रा
प्रबंध संपादक - श्री रविन्द्र अग्रवाल

मुख्य संपादक - दीपांशु गर्ग
कार्यकारी संपादक - डा. प्रदीप कुमार
संपादक मंडल - श्री राजीव रंजन
- प्रो. चन्द्रवीर सिंह भाटी
- श्री अयोध्या प्रसाद
- डा. राहुल मिश्र

डिजिटल प्रमुख - धीरज झा
डिजाइनिंग - वीरेन्द्र

प्रधान कार्यालय

सीमा संघोष
43/21, तृतीय तल, ईस्ट पटेल नगर
नई दिल्ली-110008, फोन : 9811702522
website : https://seemasanghosh.org/menu.php
e-mail : sanghoshofficial@gmail.com

Published & Printed by Vinay Gupta On behalf of SEEMA SANGHOSH Printed at B K offset F- 93, Panchsheel Garden, Navin Shahdara Delhi-110032. Publish From 43/21 3rd Floor, East patel Nagar, New Delhi 110027

प्रकाशकों और लेखकों ने सीमा संघोष की सामग्री के संबंध में अपने अधिकार सुरक्षित रखे हैं। प्रकाशकों की पूर्व लिखित सहमति को छोड़कर कोई भी कॉपीराइट कार्य किसी भी रूप या किसी भी माध्यम से पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यहां उपयोग की गई छवियां सार्वजनिक डोमेन से हैं, उनके संबंधित स्वामियों की हैं और केवल जागरूकता और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए यहां उपयोग की जा रही हैं। यह पत्रिका गैर-व्यावसायिक, गैर लाभदायक और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने का उद्देश्य लेकर प्रस्तुत की गयी है।

इस अंक में

05

अमेरिका में मोदी

07

तवांग प्रकरण और विस्तारवादी ड्रैगन की नीति-नीयत

10

ब्लू इकोनॉमी और संधारणी विकास : जी- 20 के संदर्भ में

13

मणिपुर हिंसा का वास्तविक कारण

14

उत्तराखण्ड में बढ़ती मुस्लिम आबादी

16

समय की मांग है समान नागरिक कानून

18

राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में हिन्दी

विषय सूची

अमेरिका में मोदी - पुनीत अरोड़ा.................05
तवांग प्रकरण और विस्तारवादी ड्रैगन की नीति-नीयत - डॉ. राहुल मिश्र................07
ब्लू इकोनॉमी और संधारणी विकासः जी.20... - मोहम्मद वसीम अहमद.....10
मणिपुर हिंसा का वास्तविक कारण - मनोज शर्मा...................13
उत्तराखण्ड में बढ़ती मुस्लिम आबादी -डॉ. प्रदीप कुमार...............14
समय की मांग है समान नागरिक कानून - सीमा संघोष डेस्क..............16
राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में हिन्दी - राजीव रंजन प्रसाद...........18
लेह-लद्दाख सीमा दर्शन यात्रा -डॉ श्याम नारायण पाण्डेय...22
पत्र - परमवीर केसरी................25
सीमा संवाद - आशीष शिशौदिया..........26
मंथन - डॉ. विजय कुमार चौधरी.....28

संपादकीय..................

विश्वपटल पर भारत की बढ़ती हुई ताकत के अनुमापन का यदि कोई सटीक पैमाना है तो वह हाल ही में सम्पन्न हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी ने 20-24 जून तक अमेरिका का बहुचर्चित दौरा किया। ऐसे समय में जब महाशक्तियों का दौर समाप्त हो चला है और दुनियाँ बहुकेंद्रित होने लगी है तब भारत ने अपनी सशक्त उपस्थिति वैश्विक राजनीति में दर्ज करायी है। एक दौर था जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने उनसे भेंट करने पहुंची भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को पैतालीस मिनट से अधिक प्रतीक्षा करावायी थी, आज वह समय भी विश्व ने देखा कि वर्तमान प्रधानमंत्री के लिए लाल कार्पेट बिछा कर अमेरिका प्रतीक्षा कर रहा था और उन्हें वहाँ इक्कीस तोपों की सलामी दे कर सम्मानित किया गया। इसमें संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री केवल देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी प्रसिद्ध और चर्चित हैं तथापि कथित महाशक्ति की आंख में आंख और हाथ में हाथ डाल कर चलने का जैसा सहज प्रदर्शन उन्होंने किया है, यह चीन जैसे देशों को असहज करने के लिए पर्याप्त है।

यह उल्लेखनीय है कि इस यात्रा के पश्चात दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि वे परस्पर प्रौद्योगिकी साझाकरण सहित सह-विकास और सह-उत्पादन की सुविधा प्रदान करेंगे। इस दौरे की ही उपलब्धि है कि दोनों देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, अंतरिक्ष और दूरसंचार जैसी आगामी प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में मिलकर काम करने का फैसला किया है। जहाँ तक रक्षा समझौतों का प्रश्न है भारत को अपने लड़ाकू विमान तेजस मार्क-2 के लिए नए इंजन की आवश्यकता थी। इस यात्रा में हुए समझौतों के तहत अब हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) और अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक (जीई) एयरोस्पेस मिलकर एफ-414 इंजन का भारत में सह-उत्पादन करेंगे। इसी क्रम में भारत की M-777 लाइट होवित्जर तोप हैं जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक के पहाड़ी इलाकों में चीन का मुकाबला करने के लिए तैनात हैं, उन्हें अपग्रेड करने तथा रेंज बढ़ाने का प्रस्ताव अमेरिका द्वारा दिया गया है, इससे हमारी इन तोपों की मारक क्षमता बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री के इसी दौरे की एक अन्य उपलब्धि है कि अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली स्ट्राइकर वाहन को भारत के साथ मिलकर बनाने का प्रस्ताव दिया है। स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन वस्तुत: विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली बख्तरबंद वाहन हैं जिनमें मोबाइल गन सिस्टम के साथ, 105 एमएम की तोप और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल संयुक्त है जिसके द्वारा यह टैंकों को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं भारत अमेरिका से 30 सशस्त्र 'प्रीडेटर' ड्रोन खरीदने के लिए लंबे समय से चल रहे प्रस्ताव को अंतिम रूप देने को भी तैयार हो गया है। इसके साथ ही साथ हवा से हवा में मार करने वाले अमेरिकी मिसाइल और लंबी रेंज वाले आर्टिलरी बम का निर्माण भारत में हो, इस दिशा में भी प्रगति प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है।

भारतीय दबावों और प्रभावों को इस दृष्टि से भी समझना होगा कि पिछले दिनों अमेरिका द्वारा भारत से आने वाले कई उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने और भारत द्वारा जवाबी कार्रवाई में कई अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाने के कारण व्यापार के क्षेत्र में संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। प्रधानमंत्री की वर्तमान अमेरिकी यात्रा के दौरान यह निर्णय लिया गया है कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी टैरिफ वापस ले लेगा, जो उसने अमरीका द्वारा हमारे उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने के जवाब में लगाये थे। दूसरी ओर अमेरिका भी विश्व व्यापार संगठन में भारत के विरुद्ध अपने विवाद वापस लेगा। इन तथ्यों के आलोक में हमें संज्ञान में लेना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरे में यह पल-प्रतिपल सिद्ध किया कि भारत-अमेरिका के संबंध अब बराबरी की सतह पर हैं। भारत अब विश्व शक्ति जैसे प्रतिमानों को नहीं मानता अपितु वह स्वयं अमेरिका के लिए भागीदार देश की भूमिका में है।

आपका ही
राजीव रंजन प्रसाद

अमेरिका में मोदी

पुनीत अरोड़ा (स्वतंत्र विचारक एवं सामाजिक कार्यकर्त्ता)

अमेरिका में मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका भी भारत की तरह गहरी लोकतांत्रिक संस्कृतियों वाला सुस्थापित गणराज्य हैं। इन दोनों राष्ट्रों को हिंद प्रशांत और इसके बाहर विस्तारवादी और आक्रामक चीन द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना करने के लिए एक स्वाभाविक सहयोगी बनाता है। परंतु भारत और अमेरिका के संबंध कई उतार चढ़ाव से होकर आगे बढ़े हैं। आजादी के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए कई प्रयास हुए परंतु अपेक्षाकृत परिणाम नहीं निकल सका था। परंतु बीते एक दशक से भारत की छवि जिस तरह बदली है इससे अमेरिका सहित सभी राष्ट्र इसे अपने खेमे में करने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से दोनों देशों के संबंधों में नया आयाम आया है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर कई महत्वपूर्ण समझौते हुए, जो आने वाले समय में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मदद करेंगे। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए भी बहुत उपयोगी रही। इन समझौतों में सबसे महत्वपूर्ण है जेट इंजन निर्माण से सम्बंधित समझौता। जेट इंजन टेक्नॉलजी रक्षा क्षेत्र में सबसे कठिन मानी जाती है जो अब तक केवल अमेरिका, रूस, फ्रान्स व यू.के. ने सफलता पूर्वक प्राप्त की है। अब यह प्रौद्योगिकी जल्द ही भारत के पास भी होगी व भारत अब अमेरिका के साथ संयुक्त रूप से जेट इंजन का उत्पादन करेगा। जो समझौता 2012 में केवल 58 प्रतिशत तकनीकी हस्तांतरण (ToT) के साथ प्रस्तावित था वह अब 80 प्रतिशत तकनीकी हस्तांतरण से होगा। यह न केवल अभूतपूर्व है बल्कि भारत के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण भी। GE-F414 जेट इंजन जिसका भारत अमेरिका के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करेगा वह स्वदेशी विमान तेजस एम के–2 के उत्पादन में लाभकारी होगा व जेनरेशन 5 लड़ाकू विमान बनाने में भी उपयोगी होगा।

हालाँकि एचएएल व जीई के बीच हुए इस समझौते को मूर्त रूप लेने में कुछ माह का समय लगेगा व भारत निर्मित पहला जेट इंजन लगभग 3 वर्ष में सामने आएगा। दूसरा महत्वपूर्ण समझौता है 3.5 बिलियन डॉलर का MQ-9B 'प्रीडेटर' ड्रोन समझौता जिसे भारत में संकलित किया जाएगा। जनरल एटॉमिक्स के अनुसार भारत में इसके लिए कॉम्प्रेहेन्सिव ग्लोबल एमआरओ फैसिलिटी स्थापित की जाएगी ताकि जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि अन्य देशों को भी इसकी आपूर्ति की जा सके। यह 'हन्टर किलर' MQ-9B ड्रोन जो 40 घंटे तक लगातार 40,000 फुट की ऊँचाई तक रह सकता है व हवा से जमीन पर सटीक निशाने से बम दाग सकता है, चीन के सशस्त्र ड्रोन से कई गुना अधिक सशक्त है। भारत को इस समझौते से 31 MQ-9B ड्रोन्स प्राप्त होंगे जो 15 भारतीय नौसेना व आठ प्रत्येक थल सेना व वायु सेना में प्रतिस्थापित किये जाएंगे। इन ड्रोन्स से न केवल भारतीय सेनाओं की मारक क्षमता बढ़ेगी बल्कि भारत रक्षा एवं विकास संगठन (DRDO)को स्वदेश निर्मित हाई ऐल्टिट्यूड लॉग एंडयोरैन्स (HALE) ड्रोन बनाने में मदद मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण साझेदारी है अमेरिकन अंतरिक्ष एजेन्सी नासा (NASA) व भारतीय एजेन्सी इसरो (ISRO) के बीच, जिसके अंतर्गत अमेरिका भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण देगा। अमेरिका ने आर्टेमस एकॉर्ड संधि में शामिल होने के लिए भारत का धन्यवाद भी किया व उम्मीद जतायी है कि 2024 के संभावित अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन अभियान में इसरो की भी सहभागिता होगी।

भारत अमेरिका के बीच हुए अन्य प्रमुख समझौते :

प्रौद्योगिकी – 1. भारत में अमेरिकी सेमिकंडक्टर कंपनियों के संयंत्र लगेंगे। एलएएम 60 हजार भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षित करेगी।

2. 100 भारतीय भाषाओं के लिए गूगल से एआई सपोर्ट मिलेगी।

3. भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग अमेरिका के पार्टिकल एक्सलरेटर में निवेश करेगा।

4. भारतीय कम्पनी स्टारलाइट साउथ केरोलिना में फाइबर केबल मैन्युफैक्चरिंग करेगी।

नागरिक सहयोग : 1. एच1 और एल1 वीजा नवीनीकरण के नियमों में सरलता आएगी।

2. बेंगलुरु और अहमदाबाद में अमेरिकी दूतावास तथा सीएटल और दो अन्य अमेरिकी शहरों में भारतीय दूतावास खोले जाएंगे।

3. ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में तमिल अध्ययन के लिये विभाग बनेगा।

भू राजनीतिक व अंतरराष्ट्रीय मामले : 1. भारत अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ से जुड़े छः विवाद सुलझाएँ।

2. इंडिया पैसिफिक ओशन इनीशिएटिव से जुड़ा अमेरिका।

3. भारत में नवम्बर में होगा एपीएसी का सम्मेलन।

4. इंटरनेशनल एनर्जी अलायन्स में अमेरिका भारत का सहयोग करेगा।

ऊर्जा एवं स्वास्थ्य : 1. भारत की बीएसके कोलोरैडो में सोलर मैन्युफैक्चरिंग करेगी।

2. भारत की जेएसडब्लू ओहायो में स्टील उत्पादन करेगी।

3. 10 हजार मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बसें अमेरिका लेगा।

4. कैन्सर, डायबिटीज, पैथोलॉजी के क्षेत्र में गठजोड़ होगा।

5. नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश होगा।

पिछले कुछ समय में विश्व में कई विध्वंसकारी व जटिल घटनाएँ घटित हुई जिसमें चीन की विस्तारवादी नीति व तानाशाही रवैये के कारण अपने पड़ोसी देशों से झड़पें व रूस यूक्रेन युद्ध प्रमुख हैं। जहाँ चीन व ताइवान युद्ध के कगार पर पहुँच गए और अभी भी तनाव बना हुआ है, वहीं गलवान में चीन की भारत से हिंसक झड़पें हुई। रूस यूक्रेन युद्ध से तो यूक्रेन सहित पूरा यूरोप ही युद्ध के कगार पर पहुँच गया है। ऐसे समय में दुनिया के दो बड़े लोकतांत्रिक देशों का साथ आना न केवल इन दो देशों के विकास में सहायक होगा बल्कि विश्व को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी।

तवांग प्रकरण और विस्तारवादी ड्रैगन की नीति-नीयत

आचार्य अनामय (डॉ. राहुल मिश्र) (अध्यक्ष, हिंदी विभाग केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान (सम विश्वविद्यालय) लेह)

विगत वर्ष के अंतिम माह में अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र चीन की घुसपैठ की सुर्खियों के साथ चर्चा में रहा। विस्तारवादी ड्रैगन के लिए तवांग से लगाकर लद्दाख तक की सीमाएँ एक समय में आसान निशाना हुआ करती थीं। ड्रैगन का यह भ्रम बीते वर्ष, 2022 में 09–10 दिसंबर को टूट गया होगा, ऐसा पूरे भरोसे के साथ कहा जा सकता है। तवांग घाटी में शीत के प्रकोप के साथ ही पीएलए के अंदर बड़ा जोश आ जाता है। शीत के कारण भारतीय सेना शिथिल हो गई होगी, ऐसा मानते हुए संभवतः पीएलए के जवान सीमा पर घुसपैठ के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस बार बाजी उल्टी ही पड़ गई। एक तरफ चीनी सैनिकों के पास कँटीले तार लगे हुए डंडे–लाठियाँ थीं, धारदार घातक हथियार थे, जिनसे आमने–सामने की लड़ाई लड़ी जा सके। दूसरी ओर भारतीय सेना भी गलवान का सबक लिए थी, इस कारण तैयारी यहाँ से भी पूरी थी। परिणामस्वरूप तवांग घाटी क्षेत्र के यांगत्जे नामक स्थान पर भारतीय सैनिकों ने अपने शौर्य का ऐसा प्रस्तुतीकरण किया, कि पीएलए के जवानों को उल्टे पाँव भागना पड़ा।

तवांग के यांगत्जे में लगभग 300 चीनी सैनिक सीमा पार करके घुसपैठ का प्रयास कर रहे थे। तवांग से लगभग 35 किमी उत्तरपूर्व दिशा में स्थित यांगत्जे लद्दाख की तरह ठंडा रहता है। यहाँ बर्फबारी भी हो जाती है और प्रायः मार्च तक बर्फ रहती है। यहाँ पर ही यांग्–याप दर्रा भी है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी मैदान की ओर उतरती है। इस दर्रे से होकर तिब्बत के लिए रास्ता जाता है। कुल मिलाकर यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण सामरिक स्थान है। इस कारण चीन के सैनिक यहाँ अपना जमावड़ा रखने के साथ ही घुसपैठ करके इस क्षेत्र को अपने कब्जे में लेने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसी प्रयास के तौर पर विगत माह चीन के सैनिकों ने सीमा पर अतिक्रमण किया, जिसका भारतीय सैनिकों ने मुँहतोड़ उत्तर दिया। बहुत रोचक बात यह भी है, कि भारतीय सैनिकों की प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही भारत के सोशल मीडिया के विभिन्न

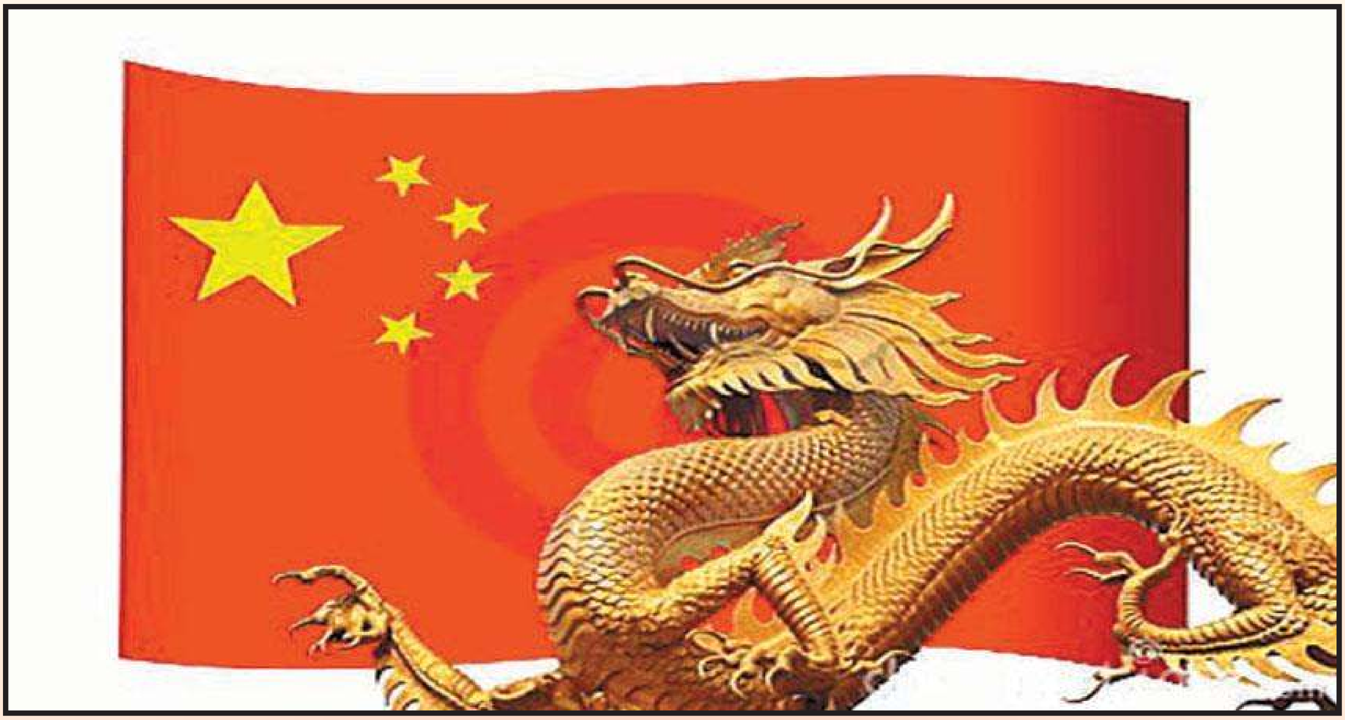

पटलों पर अनूठे तरीके से चर्चा में रही। वीडियो के साथ ही फ्लैश मैसेजेस के रूप में लोगों ने पढ़ा और जाना, कि किस तरह भारतीय सैनिकों के द्वारा न समझ में आने वाले (मंत्र जैसे) वाक्यांशों के साथ चीन के सैनिक खदेड़े गए। भारत की उत्तर–पूर्वी सीमा पर पहले भी हमारे सैनिकों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है। आम जनमानस के लिए उनकी कार्यवाईयाँ चर्चा के केंद्र में रहीं हैं, लेकिन इस बार का व्यंग्यात्मक लहजा तो देखते ही बनता है।

वस्तुतः, संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश के साथ ही विशेष तौर पर तवांग चीन के लिए दुखती रग भी है, और विस्तारवादी नीति का बड़ा लक्ष्य भी...। 21 नवंबर, 1962 को जब चीन ने अपनी तरफ से युद्ध विराम किया था, उस समय तक अक्साई चिन (लद्दाख क्षेत्र) में और पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश के सीमांतक्षेत्र को पार करके कब्जा कर चुका था। एकतरफा युद्धविराम के बाद अक्साई चिन से चीन वापस नहीं लौटा। दूसरी ओर अरुणाचल के तवांग क्षेत्र में 20 किमी पीछे मैकमोहन रेखा तक लौट गया। सन् 1980 के पहले तक ऐसा लगता था, कि ड्रैगन अपनी विस्तारवादी नीति को अक्साई चिन तक ही रखेगा, लेकिन 1980 के बाद उसकी नीयत बदलने लगी। बाद के वर्षों में पीछे लौटना चीन को घाटे का सौदा लगा हो, और इस कारण नीतियों में बदलाव किए गए हों, या अरुणाचल के तवांग क्षेत्र के सामरिक महत्त्व को देखते हुए ऐसा किया हो। कुछ भी हो, पूर्वोत्तर में 90 हजार वर्ग किमी. भारतीय क्षेत्र में चीन ने अपनी दावेदारी यह कहते हुए फिर से प्रारंभ की, कि तवांग में स्थित तिब्बती परंपरा का बौद्ध मठ उसके भौगोलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। सन् 1990 में जब भारत की उत्तर–पश्चिमी सीमा पर कारगिल का युद्ध चल रहा था, तब मौके का लाभ उठाते हुए चीन ने तवांग क्षेत्र के यांगत्जे में घुसपैठ की थी। लगभग डेढ़ महीने बाद भारतीय सेना के दखल के बाद वहाँ से हटे। सन् 2016 में भी ऐसी घुसपैठ पीएलए ने की थी। भारतीय सेना ने पुनः अपना क्षेत्र खाली कराया था। वर्ष 2021 में भी ऐसी ही घुसपैठ करने पर भारतीय सेना ने कुछ चीनी सैनिकों को बंदी बना लिया था। वर्ष 2022 में पुनः यही हुआ।

2021 की घुसपैठ में चीनी सैनिकों को बंदी बनाए जाने के बाद ऐसा प्रतीत होता था, कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति और घुसपैठ की नीयत को नियंत्रित कर लेगा। गलवान की झड़प, अक्साई चिन के प्रकरण, गोगरा हॉट–स्पाट के संघर्ष और इन सभी के कारण विश्व मंच पर होती किरकिरी के परिणामस्वरूप चीन ने बातचीत की 'टेबल' पर मामलों को निबटाते हुए सीमा पर शांति और स्थिरता की बात करनी प्रारंभ की थी। तब ऐसा लग रहा था, कि भारत की उत्तरी सीमा में अशांति का दौर समाप्त हो जाएगा। लेकिन आने वाले समय में ऐसा होता नहीं दिखा। जब चीन ने गलवान से अपने सैनिकों को पीछे हटाए जाने का संदेश दिया, तभी पूर्वोत्तर सीमा पर घुसपैठ की नीयत दिखने लगी।

तवांग क्षेत्र में चीन ने अपनी सीमाओं के पास अनेक स्थाई निर्माण करा लिए हैं। सड़क आदि संसाधनों के साथ ही सैनिकों के ठहरने, सूचना–संचार और आवागमन की सुविधाओं का

विस्तार भी किया है। इससे ड्रैगन की नीयत का पता चलता है। वह विश्व मंच पर शांति का संदेश देने के लिए गलवान से सैनिकों को वापस बुलाने का संदेश प्रसारित करता है, तो दूसरी ओर पूर्वोत्तर में घुसपैठ के सहारे अरुणाचल में कब्जा करने का ख्वाब पालता है। उसकी नीति अरुणाचल में कब्जा करके भूटान के पड़ोस तक पहुँचना है। इससे वह न केवल पश्चिमी हिस्से से चले आ रहे कॉरीडोर से पूर्व को जोड़ने की मंशा रखता है, वरन् म्यांमार को अपने अगले निशाने के लिए सहेजना चाहता है। चीन पश्चिमी क्षेत्र में डोकलाम से पूर्वोत्तर में गामोचिन तक सड़क मार्ग बनाकर पूरी उत्तरी सीमा को बृहत् कॉरीडोर के माध्यम से जोड़ना चाहता है। सड़क के साथ ही रेलमार्ग के विस्तार द्वारा वह पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। इसके लिए कम से कम अरुणाचल के तवांग क्षेत्र पर, बोमोडिला और यांग्–याप दर्रों को अपने कब्जे में लेने के लिए वह हर तरीके से प्रयासरत है। घुसपैठ की नीति भी इसी का एक अंग समझ में आती है।

अरुणाचल प्रदेश भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। बदलते सामरिक परिदृश्य में, युद्धों की रणनीति में जहाँ सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण भू–क्षेत्रों पर कब्जा करना आवश्यक है, वहीं वासुसेना की ताकत को बढ़ाना भी बहुत आवश्यक है। भारतीय वायुसेना ने इस आवश्यकता के अनुरूप अपने आधुनिकतम संसाधनों और तकनीकों का विस्तार किया है। अरुणाचल प्रदेश के हवाई–अड्डे इसी कारण चीन के लिए चुनौती बने हुए हैं। विगत वर्ष अग्नि–3, अग्नि–4 व अग्नि–5 बैलिस्टिक मिसाइलों के सफल परीक्षण करके भारत ने यह संदेश दे दिया है, कि मध्य भारत का कोई भी वायुसेना स्टेशन अपनी मारक क्षमता के अंतर्गत बीजिंग को भी ले आया है। फिर भी अरुणाचल प्रदेश के चार हवाई–अड्डे (ईटानगर, जीरो, पासीघाट, तेजू) और नौ हवाई पट्टियाँ (आला, मेचूका, पासीघाट, तवांग एयरबेस, टूटिंग, विजय नगर, वालोंग, जीरो, दापोरिज) आपात स्थिति में चीन को मुँहतोड़ उत्तर देने के लिए एकदम तैयारी वाली स्थिति में हैं। युद्ध की रणनीति में बहुस्तरीय सुरक्षा परतों का निर्माण किया जाता है, जो आक्रमणों में ढाल की तरह से प्रहार को रोकती हैं। अरुणाचल भारत के सीमांतप्रदेश के रूप में ही नहीं, वरन् ऐसी सुरक्षा–परत के रूप में भी है। छद्म युद्ध के अंग के रूप में घुसपैठ के माध्यम से ड्रैगन इस सुरक्षा–परत को भेदने की नीयत से भी अपनी गतिविधियाँ चलाता है।

विगत वर्ष अक्टूबर माह में चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय स्तर की बैठक हुई थी, उसमें चीन के राष्ट्रपति के कार्यकाल विस्तार के बराबर महत्त्व की चर्चा यदि कोई हुई, तो वह तिब्बत सीमा पर पीएलए को मजबूत करने की रही। जिनपिंग के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियों के प्रति गंभीरता दिखाने के पीछे बड़ी वजह यह भी मानी जाती है, कि वे इसके बहाने चीन के आंतरिक विद्रोह व विरोध को दबाने का काम करते हैं। कारण कुछ भी हों, भारत के लिए विस्तारवादी ड्रैगन की नीतियाँ स्वीकार्य नहीं हो सकतीं। एक समय ऐसा भी रहा, जब हम ड्रैगन के पंचशील के समझौते का निष्ठा के साथ पालन करते रहे और बदले में आघात पाते रहे, जख्म पाते रहे। अब पुरानी स्थितियाँ नहीं हैं। हमारी सेना हर तरह से मुकाबला करने के लिए मुस्तैद खड़ी है। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए देश का जन–जन साथ है।

अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र हो, या पूर्वोत्तर से लगाकर पश्चिमोत्तर तक सीमावर्ती कोई भी क्षेत्र हो..., हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा के साथ समझौता करने की नीति नहीं रखते हैं। विशिष्ट स्त्रातिजिक महत्त्व रखने वाले तवांग क्षेत्र पर ड्रैगन की विस्तारवादी और घुसपैठ की नीति–नीयत को हम भली–भाँति जानते हैं। तवांग को हथियाने के प्रयास उसके लिए आत्मघाती भी हो सकते हैं, यह उसे तवांग में ही तैनात भारतीय सैनिकों के प्रतिरोध के स्वर से समझ लेना चाहिए। भारत की वायुसेना अपनी पूरी क्षमता और अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकी संसाधनों के साथ अरुणाचल प्रदेश में तैनात है, तैयार है। विगत दिनों भारत के सेना–प्रमुख ने उत्तरी सीमा के संदर्भ में कहा था, कि– सीमा में शांति है, पर किसी भी समय कुछ भी होने की स्थिति भी है। इस कारण हम स्थितियों पर नजर रखते हुए अपनी तैयारी के साथ मुस्तैद हैं...। उनके वक्तव्य के निहितार्थ ड्रैगन के लिए संकेत हैं, उसकी घुसपैठ की नीयत के लिए संकेत हैं। तवांग भारतदेश में अरुण की पहली आभा को लेकर आता है। हमारे लिए इसी कारण प्रिय है, हमारे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय है, और उसकी ओर उठने वाली किसी भी कुदृष्टि के लिए उत्तर हमें आते हैं.... हम उत्तर देना भी जानते हैं। भारतीय सेना ने विगत दिसंबर माह में, तो केवल एक बानगी ही दी थी।

ब्लू इकोनॉमी और संधारणी विकास : जी- 20 के संदर्भ में

मोहम्मद वसीम अहमद (रिसर्च स्कॉलर (पीएचडी), अफ्रीकी अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

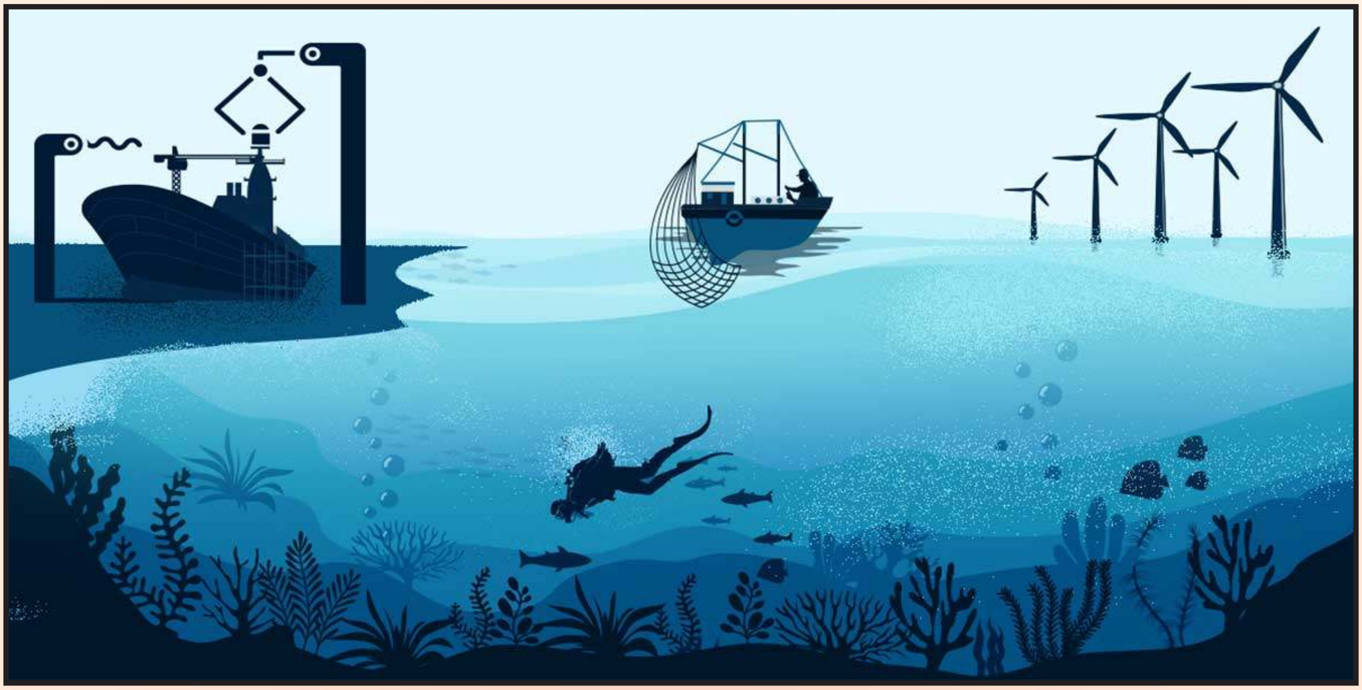

जी–20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। लैंड डिग्रेडेशन, ब्लू इकोनॉमी और सर्कुलर इकोनॉमी भारतीय अध्यक्षता के तहत चर्चा के तीन केंद्र बिंदु थे। ब्लू इकोनॉमी अनिवार्य रूप से उन आर्थिक गतिविधियों से मेल खाती है जो तटीय और समुद्री संसाधनों के उपयोग पर निर्भर करती हैं। हरित अर्थव्यवस्था की अवधारणा की तरह, यह समुद्री पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए इन संसाधनों के संतुलित और सतत उपयोग की वकालत करता है। पिछले कुछ वर्षों में ब्लू इकोनॉमी का विचार तेजी से उभर कर सामने आया है क्योंकि विश्व के देशों ने समुद्र और उसके संसाधनों की गंभीरता और जलवायु परिवर्तन, समुद्री प्रदूषण और अतिदोहन से समुद्री पर्यावरण के लिए बढ़ते खतरों को पहचानना शुरू कर दिया। वैश्विक अनुमान बताते हैं कि महासागर से संबंधित आर्थिक गतिविधियां प्रति वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 1.5 ट्रिलियन अमरीकी डालर का योगदान करती हैं। 2030 तक इसके दोगुना होकर 3 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष होने की उम्मीद है।

जी-20 देशों के लिए ब्लू इकोनॉमी की प्रासंगिकता : ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा जी–20 फोरम के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि अधिकांश जी –20 के देश तटीय राज्य हैं और आजीविका और आर्थिक विकास के लिए समुद्री संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर हैं। साथ ही वे दुनिया के लगभग 45 प्रतिशत समुद्र तट और दुनिया के 21 प्रतिशत विशेष आर्थिक क्षेत्रों के भागीदार हैं। इसलिए, जी–20 देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्थायी नीली अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डालेगा। साथ ही समुद्री पारिस्थितिक तंत्र जैसे मैंग्रोव और समुद्री घास के मैदान अत्यधिक कुशल कार्बन सिंक हैं और तटीय बाढ़, चक्रवात और समुद्र के स्तर में वृद्धि के खिलाफ प्राकृतिक बाधाओं के रूप में भी कार्य करते हैं। ब्लू इकोनॉमी के सिद्धांतों के माध्यम से इन पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण जलवायु परिवर्तन के शमन और अनुकूलन में और योगदान देगा। साथ ही इसमे मत्स्य पालन, जलीय कृषि, शिपिंग, परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन और

समुद्री जैव प्रौद्योगिकी सहित आर्थिक क्षेत्र की एक विस्तृत शृंखला शामिल है।

ब्लू इकोनॉमी की दिशा में जी-20 द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहल :

ओसाका ब्लू ओशन विजन - यह एक व्यापक जीवन–चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से 2050 तक समुद्री प्लास्टिक कूड़े से होने वाले अतिरिक्त प्रदूषण को शून्य तक कम करने का लक्ष्य है। **कोरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलेरेटर प्लेटफॉर्म** (CORDAP) – CORDAP को 2020 में लॉन्च किया गया था यह अंतरराष्ट्रीय प्रवाल संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने वाली नई तकनीकों के विकास में तेजी लाएगा।

महासागर-20 (O20) - O20 महासागर समाधान के लिए कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए जी–20 देशों के राजनीतिक नेताओं, स्थानीय और स्वदेशी समुदायों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

भारत के संदर्भ में रू भारत में नीली अर्थव्यवस्था में योगदान की व्यापक संभावनाएँ हैं। भारत के पास लगभग 7,500 किमी की लंबी तट रेख और लगभग 2.02 मिलियन वर्ग किमी का एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है जो प्रचुर मात्र में समुद्री संसाधनों और आर्थिक विकास के अवसर प्रदान करता है। भारत में नीली अर्थव्यवस्था व सतत विकास में योगदान देने वाले क्षेत्र निम्नवत हैंरू मत्स्य पालन व जलीय कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, तटीय और समुद्री पर्यटन, समुद्री जैव प्रोद्योगिकी इत्यादि।

ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा की गई पहल :

सागरमाला पहल – सागरमाला परियोजना द्वारा 'कौशल विकास' एवं 'मेक इन इंडिया' को ध्यान में रखते हुए बंदरगाहों का विकास कर औधयोगीकरण को बढ़ावा देते हुये तटीय संभावनाओं का दोहन किया जाएगा। परियोजना के माध्यम से मछुआरों एवं तटीय समुदायों के लिये भी नए अवसर सजृत होगे। यदि परियोजना के सामरिक पक्ष पर विचार करें तो यह चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल' प्रोजेक्ट के विरुद्ध भारत को बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में सामरिक दृष्टिकोण से सुरक्षा भी प्रदान करती है। सागर माला परियोजना भारत के लिये न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से अपितु सामरिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अति महत्त्वपूर्ण है।

जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति - उन्नत जहाज निर्माण ब्लू ईकॉनोमी के लक्ष्यों में से एक है। भारत में जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 1 अप्रैल, 2016 और 31 मार्च, 2026 के बीच हस्ताक्षरित अनुबंधों के लिए दस साल की अवधि के लिए जहाज निर्माण के लिए वित्तीय सहायता की नीति तैयार की है। जहाजरानी मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार जहाज की डिलीवरी के बाद पोत के अनुबंधित मूल्य, उचित मूल्य या शिपयार्ड द्वारा प्राप्त वास्तविक भुगतान के 20 प्रतिशत की दर देय है।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना - PMMSY मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित एक सतत् विकास योजना है, जिसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष 2024–25 तक (5 वर्ष की अवधि के दौरान) सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जाना है। PMMSY के अंतर्गत 20,050 करोड़ रुपए का निवेश मत्स्य क्षेत्र में होने वाला सबसे अधिक निवेश है। मछुआरों को बीमा कवर, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

डीप ओशन मिशन - इसका लक्ष्य विशेष आर्थिक क्षेत्रों (ईईजेड) और महाद्वीपीय शेल्फ में गहरे समुद्र के संसाधनों की खोज के साथ–साथ उनके दोहन के लिए प्रौद्योगिकी का विकास है। फरवरी 2019 में भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित विजन ऑफ न्यू इंडिया बाई 2030 के विजन में ब्ल्यू इकोनॉमी को वृद्धि के दस प्रमुख आयामों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। संसाधनों के लिए समुद्र की गहराईयों का अन्वेषण करने तथा समुद्री संसाधनों के संपोषीय विकास हेतु गहरे सागर में कार्य करने वाली प्रौद्योगिकियों का विकास करने के दृष्टिकोण से आर्थिक मामलों सम्बन्धी मंत्रीमण्डल समिति ने 'डीप ओशन मिशन' पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के रु 4077.0 करोड़ की अनुमानित लागत वाले प्रस्ताव को अनुमोदित किया है, जिसे चरणबद्ध तरीके से 5 वर्षों की अवधि में क्रियान्वित किया जाएगा। प्रथम चरण में 3 वर्षों (2021–2024) की अनुमानित लागत रु 2823.4 करोड़ होगी। डीप ओशन मिशन, भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करने के लिए एक मिशन मोड परियोजना होगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES)

इस बहु–संस्थागत महत्वाकांक्षी मिशन का कार्यान्वयन करने वाला नोडल मंत्रालय होगा।

तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना – तटीय क्षेत्रों का वर्गीकरण, बेहतर प्रबंधन और पारिस्थितिकी तंत्र सहित पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तटीय और समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण करना इसका मुख्य उदेश्य है। सरकार ने सतत् विकास को बढ़ावा देने तथा तटीय वातावरण के संरक्षण के घोषित उद्देश्यों के साथ नए कोस्टल रेग्युलेशन जोन (CRZ) नियमों को अधिसूचित किया। CRZ-III (ग्रामीण) क्षेत्रों के लिये दो अलग–अलग श्रेणियों को निर्धारित किया गया है।

2011 की जनगणना के अनुसार, 2,161 प्रति वर्ग किमी. जनसंख्या घनत्व के साथ घनी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों (CRZ-IIIA) में नो–डेवलपमेंट जोन, अब उच्च–ज्वार स्तर (High Tide Level) से 50 मीटर है, जो पहले 200 मीटर निर्धारित था। CRZ-IIIB श्रेणी (2,161 प्रति वर्ग किमी. के नीचे जनसंख्या घनत्व वाले ग्रामीण क्षेत्रों) में उच्च–ज्वार रेखा से 200 मीटर तक फैले नो–डेवलपमेंट जोन जारी रहेगा। नए नियमों में मुख्य भूमि के तट के पास के सभी द्वीपों और मुख्य भूमि के सभी बैकवाटर द्वीपों के लिये 20 मीटर का नो–डेवलपमेंट जोन है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम (2022) – यह देश में फैले प्लास्टिक कचरे से होने वाले प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से एकल–उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया और अपशिष्ट प्रबंधन में विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारीके लिए नीतियां प्रस्तुत की गईं। यह प्लास्टिक के नए विकल्पों के विकास को बढ़ावा देगा और व्यवसायों को सतत् प्लास्टिक पैकेजिंग की ओर बढ़ने हेतु एक रोडमैप प्रदान करेगा।

प्लास्टिक कचरे का संचय पर्यावरण के लिये हानिकारक है और जब यह कचरा समुद्र में जाता है तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र को भी बड़े स्तर पर नुकसान पहुँचाता है। भारत में सालाना लगभग 3.4 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2024 तक भारत के 100 शहरों में उनके प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को लगभग तिगुना करना है।

भारत द्वारा जी- 20 की अध्यक्षता व ब्लू ईकानमी एवं संधारणीय विकास – भारत 1 दिसम्बर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जी–20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत ने जी– 20 के होने वाले विभिन्न बैठकों में नीली अर्थव्यवस्था तथा सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। भारतीय अध्यक्षता का उद्देश्य महासागर से संबंधित मुद्दों पर पिछले जी–20 अध्यक्षता के दौरान आयोजित की गई चर्चाओं और कार्य योजनाओं को मूर्त रूप देना है। उदाहरण के लिए, हाल के वर्षों में जी–20 फोरम में समुद्री कचरा एक प्रमुख विषय रहा है। इसके आधार पर, भारत ने ब्लू इकोनॉमी के व्यापक दायरे के तहत समुद्री कचरे की पहचान एक प्रमुख प्राथमिकता के रूप में की है।

इसके अतिरिक्त, भारत ने प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और समुद्री स्थानिक योजना के संरक्षण और बहाली की पहचान की है। ब्लू इकोनॉमी के उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रभावी और एकीकृत समुद्री स्थानिक योजना (MSP) महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जी–20 फोरम में पहली बार, भारत ने एजेंडे पर एक केंद्रित मद के रूप में MSP को पेश किया है। क्रॉस–कटिंग थीम के रूप में, भारतीय प्रेसीडेंसी एक स्थायी नीली अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त के रूप में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लचीलेपन की भी वकालत कर रही है। हाल के वर्षों में जी–20 फोरम में समुद्री कचरा एक आवर्ती विषय रहा है। अब, भारत ने नीली अर्थव्यवस्था के व्यापक दायरे के तहत समुद्री कूड़े को एक प्रमुख प्राथमिकता के रूप में चिन्हित किया है।

ब्लू इकोनॉमी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मुख्य चुनौतियां व उनका समाधान – ब्लू इकोनॉमी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महासागर प्रबंधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और वित्त से संबंधित कई चुनौतियाँ हैं। समुद्री क्षेत्रों जैसे समुद्री मत्स्य पालन, जलीय कृषि, बंदरगाह और नौवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, आदि आपस में निकटता से जुड़े हुए हैं, और इन सभी क्षेत्रों को समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र में सुधार की दिशा में ठोस और स्थायी प्रभाव के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, एक देश के तट पर होने वाली गतिविधियाँ अन्य देशों के तटों पर प्रभाव डाल सकती हैं जिसे हितधारकों की सक्रिय भागीदारी और एकीकरण के माध्यम से ही संबोधित किया जा सकता है।

निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि नीली अर्थव्यवस्था और सतत विकास पर जी–20 देशों विशेषकर भारत की पहल का उदेश्य समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, और सामाजिक समावेश सुनिश्चित करना है। 2023 में जी– 20 के अध्यक्ष के रूप में भारत से नीली अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर संधारणीय विकास को बढ़ावा देने में नेतृत्वकर्ता एवं पथप्रदर्शक की भूमिका निभाने की उम्मीद है।

मणिपुर हिंसा का वास्तविक कारण

मनोज शर्मा, रीजनल सेल्स हेड, मेरठ

पिछले कुछ वर्षों से मणिपुर में कभी कभार छुटपुट भिड़ंत की घटनाएं सुनाई देती थीं परन्तु इस बार जिस प्रकार से लगातार आक्रामक रुख और हिंसक घटनाएं घट रही हैं उस पर पूरे देश में इस प्रकरण को जानने की उत्सुकता है कि आखिर माजरा क्या है, ज्यादातर लोग इसे मैतई और कुकी के बीच का झगड़ा बता रहे हैं जिसका मुख्य कारण न्यायालय द्वारा मैतेई समुदाय को एस टी का दर्जा दिया जाना बताया जा रहा है, ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन द्वारा इसके विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गयी जिसमें अभी तक लगभग 100 मौत हो चुकी हैं और लगभग 300 घायल हुए हैं वास्तविक आंकड़े शायद अलग हों, परन्तु हिंसा जबसे शुरू हुई है अभी तक शांत नहीं हो रही है, हालात देखते हुए अर्धसैनिक बलों के साथ सेना का भी जमावड़ा हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में लगा हुआ है, इसी बीच एक ऑपरेशन के दौरान हाल ही सुरक्षा बलों के विरुद्ध लगभग 1500 लोगों की भीड ने घेराव किया और 12 उग्रवादी छुड़ा लिए गए इस भीड़ में अधिकतम महिलाएं थीं इस कारण सुरक्षा बलों को पीछे हटना पड़ा क्योंकि वो रक्तपात नहीं चाहते थे, परन्तु सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक हथियारों की खेप अवश्य बरामद हुई जिसे देखकर माना जा रहा है की जैसे युद्ध की तैयारी में हों ये लोग।

यदि इसे दो समुदायों की आम झड़प समझा जाए तो इस सबके बीच अत्याधुनिक हथियार कहाँ से आए ये एक बड़ा सवाल है, केवल भारतीय जनता पार्टी से सम्बंधित नेताओं पर हमले क्यों हुए ये भी सोचने का विषय है, 60 में से 40 विधायक मैतेई समुदाय के होना भी इसका एक कारण माना जा रहा है कि कुकी जनजाति को संभवतः भड़काया गया है, 90 प्रतिशत पहाड़ी और 10 प्रतिशत घाटी क्षेत्र भी एक आंकड़ा है पहाड़ी इलाकों में मैतेई समुदाय को जमीन नहीं खरीद पाने की बाध्यता और कुकी को घाटी में जमीन खरीदने की छूट भी एक कारण माना जा रहा है, म्यांमार और बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ से उत्पन्न असुरक्षा का भाव अन्य कारण में शामिल है परन्तु इस सबके बीच सुनियोजित रूप से सत्ता के विरुद्ध हथियारों से लैस संगठन का निर्माण और उन्हें समर्थन करते सामान्य लोग एक अलग दृष्टिकोण विकसित कर रहा है, कुछ जानकारों का मानना है कि अफीम की अवैध खेती का खेल वर्तमान सरकार ने अवरुद्ध कर दिया है जिस कारण इस खेल के खिलाड़ियों द्वारा जनजातिय संघर्ष की आड़ लेकर अपनी कुंठा को शांत करने के लिए मणिपुर को दंगों की आग में धकेला गया है यह भी एक थ्योरी है। कारण कोई भी हो परन्तु निवारण होना आवश्यक है जिसके प्रयास सरकार द्वारा शुरू हो चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे हस्तक्षेप के बाद उम्मीद है की जल्दी समस्या का निवारण कर लिया जायेगा।

उत्तराखण्ड में जनसंख्यात्मक असमानता

डॉ. प्रदीप कुमार (असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, रामजस कॉलेज, दिल्ली विवि.)

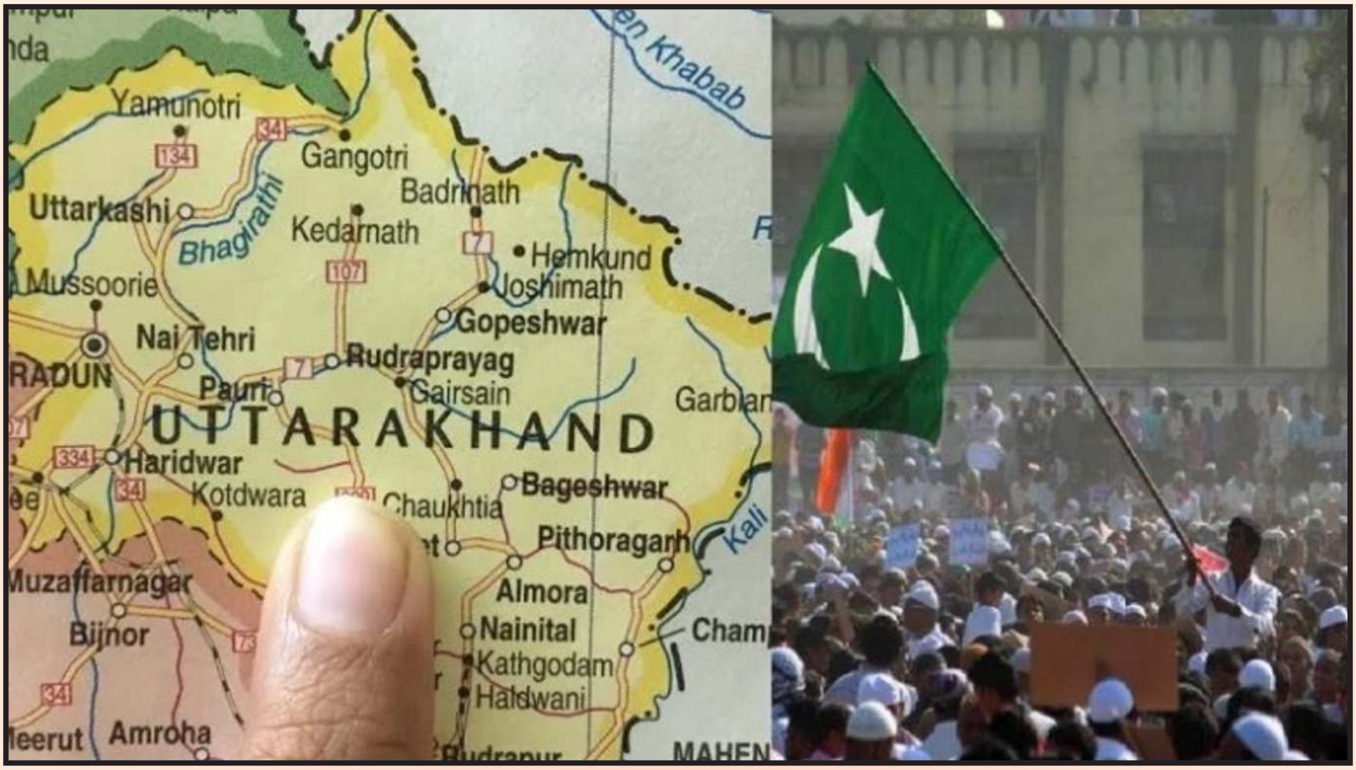

उत्तराखंड में क्या किसी षड्यंत्र के तहत मुस्लिम आबादी बढ़ रही है? सुदूर पहाड़ी कस्बों में मस्जिदें, मजारें देवभूमि उत्तराखंड में किसके इशारे पर, किसके संरक्षण में बनती जा रही हैं? सूत्र बताते हैं कि चौंकाने वाली इस खबर की जानकारी आई बी ने केंद्र को दी है, जिस पर और जानकारी जुटाई जा रही है।

उत्तराखंड राज्य बने बीस साल से ज्यादा का समय हो चुका है। इस दौरान राज्य में मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ी है। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में 11.9 प्रतिशत मुस्लिम आबादी थी, जोकि 2011 में बढ़ कर 13.94 प्रतिशत हो गयी। अकेले हरिद्वार जैसे तीर्थ जिले में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। यहां मुस्लिम आबादी दर दो गुने से ज्यादा हो गयी। इसके पीछे वजह है हरिद्वार जिले से लगते उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बाहुल्य जिले मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद आदि से बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी यहां आकर बसी। 2011 में हरिद्वार जिले में मुस्लिमों की आबादी 1,89,0422 थी, अब यह 4,78,000 को पार गर गई है।

यूपी से लगे उधमसिंहनगर जिले में भी पिछले बीस साल में बरेली, रामपुर, पीलीभीत, बिजनौर आदि जिले से आये मुस्लिम आबादी की बसावट बड़ी संख्या में दर्ज की गई है। जिले की 35 फीसदी आबादी मुस्लिम 2023 में हो जाने का अनुमान है। इसी तरह देहरादून जिले की मुस्लिम आबादी 34 प्रतिशत के आसपास हो जाएगी।

पूरे राज्य का यदि आंकलन करें तो मैदानी चार जिलों में मुस्लिम आबादी तीस प्रतिशत के पार हो रही है, जबकि पहाड़ों के अन्य नौ जिलो में मुस्लिम आबादी की बसावट 2001 से 2011 तक कम थी लेकिन 2022 तक इसमें भी अप्रत्याशित वृद्धि होने की बात कही जा रही है। जिस पर आई बी ने केंद्र को चेताया है कि सुदूर सीमावर्ती जिलों में ही मुस्लिम आबादी की बसावट हो रही है। वेल्डर, मैकेनिक, राजमिस्त्री, मजदूर, कार पेंटर, सब्जी विक्रेता के छोटे

कारोबार करने वाले तिब्बत चीन नेपाल सीमा तक जा बसे हैं। सस्ती जमीन मिल जाने के लालच में मुस्लिम आबादी के बसने की एक बड़ी वजह है। हाल ही में एक और रिपोर्ट भी सामने आई है कि पहाड़ों में वन भूमि पर मजारें बनाई जा रही हैं। टिहरी झील के आसपास ऐसी मजारें देखने मे आयी हैं। कुछ ऐसे शहर, कस्बे भी चिन्हित किये गए हैं, जहां मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। यहां मजारें बनाई जा रही हैं, उनकी आड़ में लोग बस रहे हैं। रामनगर, कालाढूंगी, टनकपुर बनबसा, चंपावत, भवाली, बागेश्वर, धारचूला, कोटद्वार, पौड़ी, श्रीनगर, सतपुली, पिथौरागढ़ वे पहाड़ी इलाके हैं, जहां सुनियोजित ढंग से मुस्लिम आबादी की बसावट हो रही है। यहां मजारें, मस्जिदें कैसे बन गईं, जबकि उत्तराखंड ही नही पूरे देश में किसी नए पूजा स्थल के निर्माण पर रोक लगी हुई है। उत्तराखंड के किच्छा, लक्सर, ज्वालापुर, खटीमा, सितारगंज, रुद्रपुर, जसपुर, सुल्तानपुर पट्टी, गदरपुर, हल्द्वानी आदि कस्बे ऐसे हैं जोकि भविष्य में करीब 33 फीसदी मुस्लिम आबादी वाले हो जाएंगे।

2011 में देश की जनगणना रिपोर्ट में 2001 से 2011 के बीच 0.8 फीसदी मुस्लिम आबादी वृद्धि दर सामने आई। सबसे ज्यादा असम में 3.3 फीसदी की मुस्लिम आबादी वृद्धि दर दर्ज हुई और उसके बाद उत्तराखंड में, जहां 2 फीसदी मुस्लिम आबादी वृद्धि दर सामने आई। इसके बाद केरल में 1. 9 प्रतिशत,बंगाल में 1.8 फीसदी वृद्धि दर मुस्लिमों की सामने आई। उत्तराखंड के पहाड़ों से स्थानीय लोगों का पलायन पिछले बीस साल में तेजी से हुआ है। रोजगार की तलाश में पहाड़ के लोग मैदानी इलाकों की ओर रुख कर चुके हैं। पहाड़ों पर खाली हुए खेत खलियानों में मुस्लिम आबादी की नजर है, ऐसा खुफिया रिपोर्ट में बताया गया है! ऐसी भी जानकारी में आया है कि मजदूरों के रूप में रुहेला, बांग्लादेशी मुस्लिम लोग यहां आकर बस चुके हैं। वोटों की राजनीति के चलते मतदाता सूची में इनके नाम चढ़ रहे हैं और आधार कार्ड भी बन रहे हैं।

उत्तराखंड में लव जिहाद, धार्मिक स्थलों के बारे में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने को लेकर भी घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। पिछले दिनों पौड़ी गढ़वाल के सतपुली इलाके में कोटद्वार में तनाव हुआ। अभी हाल ही में हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज परिसर में एक मजार को लेकर विवाद सामने आया। टिहरी झील के पास बनीं मजारों में देवताओं के नाम तक लिख कर स्थानीय लोगों को भ्रमित किया गया।

कांग्रेस के शासन काल में जब हरीश रावत की सरकार थी तब एक अभियान के तहत मैदानी जिलों में मुस्लिम वोट बैंक बढ़ाने का अभियान भी गुपचुप तरीके से चलाया गया, जिसकी चुनाव के समय जबर्दस्त प्रतिक्रिया भी हुई और हरीश रावत किच्छा और हरिद्वार की दोनों विधानसभा सीटों पर चुनाव हार गए। ऐसा ही देहरादून और रुड़की सीटों पर भी हुआ। बहरहाल, आई बी की रिपोर्ट गौर करने वाली है। केंद्र और राज्य सरकार को इस पर ठोस योजना बनानी होगी और भूमि संबंधी कानूनों पर पुनर्विचार करना होगा।

समय की मांग है समान नागरिक कानून

सीमा संघोष डेस्क

समान नागरिक कानून का सामान्य आशय है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए समान कानून होना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति के क्यों ना हो? समान नागरिक कानून लागू होने से शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में सभी भारतीयों के लिए एक जैसे नियम होंगे। समान नागरिक संहिता एक देश व एक विधान की विचारधारा पर आधारित है। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत देश के सभी व्यक्तियों को हर धर्म, जाति, संप्रदाय और वर्ग के लिए संपूर्ण देश में एक ही कानून है। समान नागरिक कानून का आशय है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद के लिए नियम एक ही होंगे।

देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी समान नागरिक कानून की उपादेयता को लोकतांत्रिक शासन व लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण बताया है, हालांकि साल 1967 में भारतीय जनता दल (तत्कालीन जनसंघ) ने अपने आम चुनावी घोषणा पत्र में पहली बार 'समान नागरिक संहिता' को सम्मिलित किया था। चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया था कि अगर जनसंघ सत्ता में आती है, तो देश में समान नागरिक संहिता को क्रियान्वित किया जाएगा। भारतीय राजनीति में एक ऐसा दौर आया जब राजनीतिक विचारधारा पर संकट के बादल छा गये और राजनीतिक नेतृत्व को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस का बंटवारा, भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 और आपातकाल का दौर (25 जून,1975) इन सभी के बदलते आयाम में भारतीय जनता दल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण (स्थापना की ओर अग्रसर) है और अनुच्छेद 370 (जम्मूकश्मीर का विशेष प्रावधान) और समान नागरिक कानून (अनुच्छेद 44) को भारतीय जनता दल ने अपने मुख्य चुनावी एजेंडा, भारतीय जनता दल को इन मुद्दों पर जनमत/लोकमत ने सहयोग दिया और वर्तमान राजनीतिक पाठशाला में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, कुशल संगठन, चुनावी पांडित्य के विशेषज्ञ और राजनीति के चाणक्य जैसे अलंकारों से जनता जनसभाओं

में भी घोषित किए जा रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पश्चात मोदी जी ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व, करिश्माई नेतृत्व हैं जिनको राजनीति में जनता इतनी विश्वास कर रही है। मोदी जी के कार्यक्रम में लोक संस्तुति/जन संस्तुति व्यापक होती है।

इसी क्रम में बीते 27 जून, 2023 को 'सबसे मजबूत संवाद' में समान नागरिक संहिता पर विस्तृत तरीके से जनता से संवाद किए थे। भोपाल में एक जन संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि "एक ही परिवार में दो लोगों के लिए अलग–अलग नियम नहीं हो सकते। ऐसी दोहरी व्यवस्था से परिवार कैसे चल पाएगा?" मोदी जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास पर आधारित लोकतांत्रिक मंत्र पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वर्ष 2024 में "समान नागरिक संहिता बीजेपी का परमाणु बटन" सिद्ध हो रहा हैं, क्योंकि 2014 के आम चुनाव में बहुमत एवं वर्ष 2019 का आम चुनाव में बहुमत चुनावी मुद्दे की जीत थी। समान नागरिक संहिता जनसंघ के समय से ही चुनावी मुद्दा रहा है। अनुच्छेद 370 और राम मंदिर के मुद्दे लागू हो चुके हैं। विपक्षी पार्टियों की एकजुटता का संकेत बीतें 23 जून को मिला था, लेकिन उनके पास सर्वमान्य मुद्दे का अभाव है, इसलिए विपक्ष को मोदी जी ने चुनावी रणनीति से रिएक्टिव बना दिया है। जो दलितों और अल्पसंख्यकों को 2024 में आकर्षित करने में महत्वपूर्ण साथन सिद्ध होगा। भारतीय जनता पार्टी (तत्कालीन में जनसंघ) सार्वभौमिक रूप से एक देश, एक विधान एवं एक निशान की बात करती है।

जब देश में समान आपराधिक संहिता सबके लिए समान है तो भारतीय नागरिक संहिता अलग–अलग क्यों होगी? प्रायोगिक स्तर पर गोवा देश का इकलौता राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है, और सफल भी है। इधर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार कर लिया है। वैश्विक स्तर पर आधुनिक और विकसित राज्य समान नागरिक कानून को अपने देश में लागू किए है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, जापान, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों में समान नागरिक संहिता कानून लागू है। इस्लामिक देशों की बात करें तो तुर्की को छोड़कर सभी देशों में शरिया कानून है, जो सभी धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू होता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में हिन्दी

राजीव रंजन प्रसाद (उपमहाप्रबंधक (पर्यावरण), एनएचपीसी लि.)

चीन में नाशपाती के फलों पर एक प्रयोग हुआ। भगवान बुद्ध की आकृति का सांचा बनाया गया और नन्हें फलों को वास्तविक आकार लेने से पहले, उनपर वह कस दिया गया। फल जैसे जैसे आकार–प्रकार में बड़ा होता गया उसकी, बाध्यता थी कि वह अपना विस्तार सांचे की परिधि के भीतर ही करे। फल की अपनी कोई इच्छा नहीं थी, उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं, उसकी नियति तय थी कि बुद्ध की तरह दिखना है। सोचता हूँ कि क्या जैसा दिखता है वही वास्तविकता होती है? आज जिस शिक्षा–प्रणाली को हमने आत्मसात किया है, क्या वह ऐसा ही सांचा नहीं है? बच्चा क्या आकार लेना चाहता है इसकी किसे चिंता है? कल्पनायें, आकांक्षायें और नैसर्गिक प्रतिभा ने उसे किसलिये गढ़ा है उसे यह सांचा समझने की क्षमता नहीं रखता, उसके लिये तो बच्चा नाशपाती है और बुद्ध का आकार दिया जाना है। क्या हमारी शिक्षा प्रणाली के पास कोई उद्देश्य था अथवा सांचा ही? ध्यान से देखें तो आज की शिक्षा अक्षरज्ञान का आधुनिक संस्करण भर लगती है। वह चाहे साहित्य हो, विज्ञान हो अथवा गणित, सांचों ने सीधा देखना सिखाया है। घोडे की आँख केवल आगे ही देखने के लिये प्रशिक्षित की जाती हैं, उसे दायें–बाएं के परिदृश्य से अवरोधित किया जाता है जिससे वह अपनी लीक न छोड़े। ऐसे ही हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली जटिल प्रशिक्षण है कि कैसे बने हुए कदमों के निशानों पर ही कदम रखे जाने हैं, रास्ते तय हैं और मंजिले निर्धारित। ऐसी प्रणालियों में भाषा की स्थिति तो शिक्षण को और भी जटिल बना देती है। फैशन ने स्कूलों को फाईवस्टार और अध्यापन की भाषा को बाध्यकारी रूप से अंग्रेजी बना दिया है। इस परिप्रेक्ष्य में सोचिये कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था सोने का पिंजरा नहीं है जिसमें हम सहर्ष अपने परिंदे जैसे बच्चों को कैद कर रहे हैं। उसे प्रशिक्षित कर रहे हैं कि वह उडान भूल जाये, आकाश का सपना न देखे, जमीन से परिचित न हो सके? वह जो रटाया जाये रटे, जो सिखाया जाये सीखे और जैसा समझाया जाये वैसा ही और उतना ही बरताव करना मैनर्स समझे।

जिसने भी "निज भाषा" का महत्व समझा है, उत्कर्ष को

प्राप्त किया है। अपनी भाषा ही सोचने समझने का सबसे सटीक माध्यम हो सकती है, जबकि आयातित भाषा विद्यार्थी से दो कार्य एक साथ करवाती है, पहला अनुवाद तत्पश्चात उसका कहना। जब हम किसी आयातित भाषा को शिक्षा का माध्यम बना कर थोपने का प्रयत्न करते हैं तो अच्छे नंबर लाने की बाध्यता वाली प्रणाली के माध्यम से बचपन को जटिल काम थमा देते हैं, रटते रहो, भले ही विषय की समझ बना पाए अथवा नहीं। भाषा ही जब असमानता का कारण बन जाये, जब एक साम्राज्यवादी देश की भाषा के माध्यम से शिक्षित विद्यार्थी दंभ भरे कि वह श्रेष्ठ और हिन्दी सहित भारतीय भाषाओं से पढ़े विद्यार्थियों को हेय माना जाए और ऐसा स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने लंबे समय के बाद भी होता रहे, तब पूरी व्यवस्था को ही चुल्लू भर पानी की आवश्यकता है। भारत जब आजाद हुआ तब तक भी संस्कृत विद्यालय बड़ी मात्रा में थे। वे विद्यार्थी जिन्हें अंग्रेज और अंग्रेजीयता से विद्वेष था उनके लिए संस्कृत सहित भारतीय भाषाओं में अध्यापन प्रदान करने वाले विद्यालय उपलब्ध थे। अंग्रेज गए और अंग्रेजीयत के हम गुलाम हो गए लेकिन क्यों? आज भारतीय कार्यपालिका को भारतीय भाषाओं में काम करने में कठिनाई है, भारत की न्यायपालिका को भारतीय भाषाओं में काम करने में कठिनाई है ऐसे में तो बाध्यता ही है न कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना जाए? शायद इसलिए स्वाधीनता के बाद का वह पहला प्रसिद्ध भाषण जो आधीरात को भारत के पहले प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी में दिया था दरअसल बुनियाद बना कि अंग्रेजी ही रहेगी शिक्षा का माध्यम।

हमने भाषा को लेकर शिक्षानीतियों में अब तक क्या किया है? क्या हमारी शिक्षा प्रणाली के पास कोई उद्देश्य था, भाषा को लेकर कोई स्पष्टता थी अथवा सांचा ही? पहले 10+2+3 का सांचा था बदल कर 10+2 हो गया, इससे व्यावहारिक बदलाव क्या आया? बच्चे छः–सात वर्ष की आयु के पश्चात से बुनियादी शिक्षा की दुनियाँ में अपना पहला कदम रखते थे फिर तय हुआ कि पहली कक्षा अर्थात् पाँच साल की आयु। इतनी छोटी आयु वर्ग की शिक्षा के लिये हमने कैसी दुनियाँ बनायी? उसने गिटर–पिटर ही क्यों पढ़ाना चाहते हैं? क्या जो पाठ्यपुस्तकें इस आयुवर्ग के लिये निर्धारित की गयी हैं वे उनकी सहज उड़ान में योगदान देती हैं अथवा रट्टू तोता ही बना रही हैं? इतने से भी मन नहीं भरा, कुछ शिक्षाशास्त्रियों को अब यह लगने लगा कि स्कूल में प्रवेश से पहले से ही बच्चे की बुनियाद सही होनी चाहिये अर्थात् उसे सब कुछ पहले से आना चाहिये जिसके लिये वह किसी महान स्कूल की पहली कक्षा में प्रवेश लेगा। यहाँ भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना ही केन्द्रीय लक्ष्य था। इसके तहत हमने केजी और नर्सरी के कॉन्सेप्ट को आयात किया और अंग्रेजी के फावड़े से बच्चे की बुनियाद को तबीयत से खोदने लगे। जब नर्सरी और केजी जैसी कक्षाओं में भी ग्रेड और नम्बर की स्पर्धा हो गयी तो प्री–स्कूल या प्री–नर्सरी का विचार सामने आ गया। मुझे डर है आने वाले समय में "आफ्टर बर्थ स्कूल" और "इनसाईड–बूम्ब स्कूल" की अवधारणायें सामने न आने लगें। ऐसा होने पर हो सकता है मातृभाषा वाली समस्या का समाधान हो जाए, "इनसाईड–बूम्ब स्कूल" का बच्चा संभव है अंग्रेजी रटा–समझा ही जन्म ले? इस परिप्रेक्ष्य में सोचिये कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था सोने का पिंजरा नहीं है जिसमें हम सहर्ष अपने परिंदे जैसे बच्चों को कैद कर रहे हैं। उसे औपनिवेशिक मनोवृति, तरीके और भाषा से प्रशिक्षित कर रहे हैं कि वह उडान भूल जाये, आकाश का सपना न देखे, जमीन से परिचित न हो सके? वह जो रटाया जाये रटे, जो सिखाया जाये सीखे और जैसा समझाया जाये वैसा ही और उतना ही बरताव करना मैनर्स समझे। आश्चर्य होता है न कि पंचतंत्र भारत देश की कृति है? तीसरी सदी की रचना पंचतंत्र, आज के समय में हर्गिज नहीं लिखी जा सकती क्योंकि नाशपाती वाले बुद्ध तो कभी कल्पना नहीं कर सकते अलबत्ता वे 'सौ बटा सौ' अवश्य लाते हैं। इन कथित मेधावियों की प्रतिबद्धता ही अपने राष्ट्र के प्रति न्यूनतम रहती है, उन्हें तो अमेरिका और ब्रिटेन की सेवा करना श्रेयस्कर लगाता है, आखिर उनकी भाषा में वे दक्ष जो हैं।

शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं को लेकर अब तक रही अस्पष्टता की भी थोड़ी पड़ताल कर लेते हैं। मैकाले पर बहुत चर्चा हुई है परंतु आजादी के पहले की बातों की लकीर कब तक पीटी जाएगी। स्वतंत्रता के पश्चात क्रमशः तीन आयोग बने–राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग और कोठारी आयोग। सिफारिशे लागू हुई लेकिन बहुत उत्साहवर्धक परिणाम

नहीं थे। वर्ष 1986 में लागू की गई शिक्षा नीति के संबंध में कहा जा सकता है कि यह प्राथमिक बदलाव था। यह पहल ही बड़ी बात थी चूंकि यह नीति स्वतंत्र शिक्षा को मूल्यपरक बनाने और उसे भारतीय संस्कृति से एकाकार करने की बात करती थी तथापि इसमें क्रियान्वयन की कोई योजना प्रस्तुत नहीं की गई। अनेक विद्वान मानते हैं कि वर्ष 1986 की शिक्षा नीति 'यूरोसेंट्रिक' थी। इसमें भारतीय जीवन और भारतीय समाज का कोई आकलन किए बिना, यूरोप से आ रही हवा का अनुकरण करने की कोशिश की गई थी। इसका सीधा सा अर्थ यही था कि भाषा के स्तर पर कोई स्पष्टता नहीं थी और अंग्रेजी ने अपना प्रभुत्व केवल बनाए ही नहीं रखा अपितु भारतीय भाषाओं को सुरसा बना कर निगल गई।

इस बात को स्पष्ट करने के लिए अपना ही एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ। देहरादून स्थित शैमरॉक प्री–स्कूल में मैने अपने बेटे का प्रवेश कराया था। प्री–स्कूल का अर्थ क्या है? विद्यालय में प्रवेश से पूर्व बच्चा खेले–कूदे, हम उम्र बच्चों के बीच मिले–जुले और इस तरह जो सिखाया जा सकता है उसी माध्यम से उसकी बुनियाद इस तरह गढ़ी जाये कि अध्ययन में अभिरुचि हो। इसके ठीक उलट मुझे डायरी में बार–बार नोट मिलते कि पालक ध्यान दें, बच्चा याद नहीं कर रहा है या कि स्कूल में आ कर मिलें। मैंने हाजिरी लगाई तो वही रोना फाईव फ्लावर याद नहीं हैं, फाईव एनिमल के नाम नहीं बोल पाता, फाईव प्लांन्ट्स के नाम याद कराईये। मैं देख रहा हूँ कि बस्ता भारी वाली पीढ़ी बढ़ती ही जा रही है। ये कैसे प्ले स्कूल हैं और कैसे खेल खिला रहे हैं? बच्चा प्लांट की जगह पौधा समझे तो क्या दिक्कत? नयी पीढ़ी से मुझे सहानुभूति है जिसे इस तरह पीसा जा रहा है मानो ब्लैक लैटर्स नहीं बफैल्लो हो। हमारे देश का ब्लैकबोर्ड ही ब्लैकआउट हो चुका है और हम गुमान में हैं कि कुछ सिखा–पढ़ा रहे हैं। बच्चे की हिन्दी और अंग्रेजी विषयक किताबें पलटकर देखता हूँ तो कुछ जाना–पहचाना प्रतीत होता है। अंग्रेजी या कि हिन्दी की पाठ्य पुस्तक में जो भी कहानियाँ हैं, सभी पंचतंत्र का ही विकृत अनुवाद भर तो है? नया क्या है? दो–ढ़ाई हजार साल पुरानी सामग्री है यह जिसे मॉडर्न एज्यूकेशन के नाम पर रिमॉडल किया गया है। हमें क्या? बच्चा ऐसे नामी–गिरामी स्कूल में पढ़ रहा है न जिससे कि स्टेटस सिम्बल बनता हो? हम शिक्षा जगत के उन रंगे सियारों को अब भी नहीं पहचानते जिन्होने हमारे बच्चों को ट्विंकल–ट्विंकल लिटिल स्टार पोयम बाईहार्ट करा दिया है। सत्तर साल पहले ही अंग्रेज भारत से गये, अब तो मैकाले को कंधे से उतारा जाये?

लाख टके का सवाल है कि मैकाले का बैताल कंधे से उतरे तो उतरे कैसे? पहले हमने संस्कृत को स्वयं अपनी उपेक्षा से मारा और अब हिन्दी ही हो रही हत्या पर चुप्पी लगाए बैठे हैं। मेरे पास कक्षा दसवी की वर्ष 1975 में पढ़ाई जा रही हिंदी की पुस्तक परिमल के दोनो भाग सुरक्षित हैं (चूंकि मेरे पिता उन दिनों केंद्रीय केंद्रीय विद्यालय में भाषा के अध्यापक थे)। साथ ही मैंने वर्ष 1986 में दसवीं की कक्षा उत्तीर्ण की है अतः मध्यवर्ती पाठ्यक्रम से मैं अवगत हूँ। इस आलोक में मैं आज कक्षा दसवीं के हिन्दी पाठ्यक्रम की विवेचना करता हूँ तो आश्चर्यजनक रूप से नवीन पुस्तकों में न्यूनतम शोध और अटपटा चयन दृष्टिगोचर होता है। अगर रीतिकाल के कवि देव की चयनित रचनायें दुरुह थीं तो पाठ्यक्रम निर्माताओं को यह अहसास क्यों नहीं था? उनकी कोई अन्य रचना पढ़ाई जाती? कक्षा दसवीं में पढ़ाये जा रहे केवल कविता वाले खण्ड की तुलना करते हैं अर्थात परिमल (1975) और क्षितिज (2018)। परिमल के कवि हैं – कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, भारतेंदु हरीश्चंद्र, अयोध्यासिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, निराला, दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, अज्ञेय, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, डॉ. शंभुनाथ सिंह तथा केदारनाथ सिंह। केवल कवियों का ही नहीं रचनाओं का चयन भी शानदार है, जहाँ कबीर के क्रांतिकारी दोहे हैं, मीरा की भक्ति है, भारतेंदु हरीश्चंद्र की "जगत में घर की फूट बुरी" जैसी रचनायें हैं, "एक फूल की चाह" जैसी आँखे नम कर देती सियाराम शरण गुप्त की कविता है, "मेरे नगपति मेरे विशाल" का हुंकार करते दिनकर हैं तो "रुक सी गयी प्रगति जीवन" की समझाते केदारनाथ सिंह है। यह पुस्तक कविता के तीनों कालखण्डों ही नही विचारधाराओं की भी तुला पर सटीक बैठती है जहाँ छात्र के भ्रमित होने की कम ही गुंजायिश है। ऐसी–ऐसी रचनायें ली गयी हैं कि कविता विधा से स्वतः ही छात्र जुडेगा अपनी समझ विकसित करने लगेगा। पुरानी होने के कारण मेरे पास यह पाठ्य पुस्तक बहुत जर्जर अवस्था में है अतः सम्पादकों मे केवल डॉ. बरसाने लाल चतुर्वेदी ही पढ़ सका हूँ।

अब वर्ष 2023 में कक्षा दसवीं का पाठ्यक्रम कैसे रचनाकार और किन कवियों को समाहित किये हुए है यह जानना आवश्यक है। सूरदास, तुलसीदास, निराला, नागार्जुन, गिरिजाकुमार माथुर, ऋतुराज और मंगलेश डबराल अर्थात केवल सात कवि। पाठ्यक्रम कितना शोधपरक है यह समझें कि तुलसीदास का "लक्ष्मण–परशुराम संवाद" पिता ने 1986 में कक्षा दसवी मे पढ़ा था अब पुत्री भी वही पढ़ रही है।

पूरे रामचरितमानस–विनयपत्रिका अथवा अन्य रचनावलियों में झांकने की और विविधता प्रदान करने की दशकों में आवश्यकता महसूस नहीं हुई, क्यों? बदले कौन जाते हैं तो वे हैं आखिरी के पन्नों वाले कवि, जहाँ किसे अमरत्व प्रदान किया जाये वाली जोर आजमायिश रहती है। ऐसे में ऋतुराज की कन्यादान और मंगलेश डबराल की संगतकार जैसी रचनायें अपना स्थान बना लेती हैं। समग्रता और स्तरीयता की दृष्टि से देखें तो परिमल (1975) के समक्ष क्षितिज (2018) बहुत हलका जान पड़ता है। जब मैं पाठ्यपुस्तक निर्माण समीति की सूची देखता हूँ तो आश्चर्य करता हूँ कि अध्यक्ष है – डॉ. नामवर सिंह और मुख्य सलाहकार हैं डॉ. पुरुषोत्तम अग्रवाल।

दो राय नहीं कि परिमल और क्षितिज की कोई तुलना नहीं,

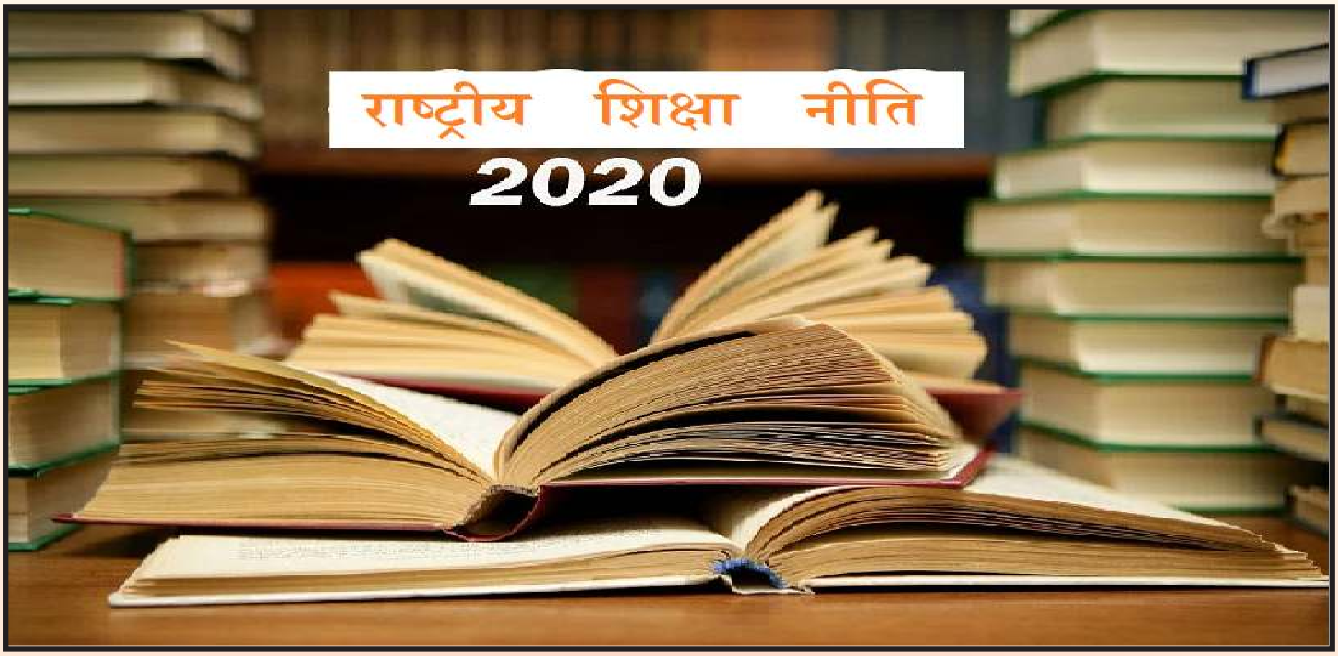

एक उत्कृष्ट तो दूसरे को बेहद हलकी की श्रेणी में रखा जा सकता है। पाठ्यक्रम कम करने के नाम पर स्तर कम करने की समझायिश देने वाले कौन और कैसे विद्वान हैं? पाठ्यक्रम स्कूली छात्रों को विचारधारा की चाशनी चटाने से बाज नहीं आता, क्यों? कवियों–महाकवियों को चुनने का प्राधिकार जिनके पास है क्या वे यह मान कर चले हैं कि अच्छी रचनायें बच्चों को पढ़ायी ही नहीं जानी हैं? चाहे नागार्जुन की कविता हो या कि ऋतुराज की अथवा मंगलेश डबराल की, सभी औसत कवितायें ली गयी हैं, क्यों? क्या भाषा शिक्षा का यह स्तर जान–बूझ कर बनाया जा रहा है? अथवा जिन लोगों को पाठ्यपुस्तक में क्या होना चाहिये इसके चयन के लिये इकट्ठा किया गया है वे इस योग्य ही नहीं? अगर बच्चे ही औसत अथवा बोरियत भरी रचनायें पढ़ेंगे तो उनसे क्या यह अपेक्षा है कि वे अपने समय के साहित्य को कोई योगदान देंगे? चीखते रहिये कि हिंदी में अच्छा नहीं लिखा जा रहा है लेकिन सच्चाई यह है कि हिंदी में अच्छा पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। मेरा आरोप है कि पाठ्यपुस्तकें विचारधारा की चटनी हो गयी हैं जिन्हें चटा चटा कर हिंदी को स–प्रयास मारा जा रहा है।....और इसके दोषी वे लोग हैं जिन्हें हमारे बच्चों के पाठ्यक्रम बनाने के लिये चुना गया है।

ये उदाहरण मैंने अपने आसपास के ही दिए हैं और जानता हूँ, कि कमोबेश यही अनुभव सभी का है। अब कुछ आशावादिता नहीं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के कारण जगने लगी है। यह नीति इस तथ्य को रेखांकित करती है कि शिक्षण भारतीय जन, भारतीय समाज तथा भारत राष्ट्र के अनुरूप हो। प्रसन्नता इसबात की है कि नीति नें बहुत स्पष्टता से भारत की बहुभाषिकता को समाहित किया है। भारत सरकार द्वारा शिक्षा माध्यम के रूप में भाषा की शक्ति को पहचानते हुए विभिन्न प्रावधान व सुझाव इस शिक्षा नीति में किए गए हैं। विशेष रूप से यह रेखांकित किया गया है कि ”छोटे बच्चे अपनी मातृ भाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं और समझ लेते हैं। ऐसे में जहाँ तक संभव हो, कम से कम ग्रेड 5 तक लेकिन बेहतर यह होगा कि यह ग्रेड 8 और उससे आगे तक भी हो, शिक्षा का माध्यम, घर की भाषा/ मातृ भाषा/ स्थानीय भाषा/ क्षेत्रीय भाषा होगी। इस नीति के अनुसार सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के विद्यालय इसकी अनुपालना करेंगे। यही नहीं इस नीति के तहत विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतम गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकों को मातृ भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। त्रिभाषा का सिद्धांत पूर्व की शिक्षा नीति में भी था किन्तु क्रियान्वयन की धारा नहीं थी। नई नीति के तहत शिक्षण में कम से कम दो भारतीय भाषाएं होगी। शिक्षण, शोध, अनुसंधान, काम–काज और संप्रेषण की भाषा के विकल्प के रूप में हिंदी को मजबूत करने का कार्य भी इस नीति का उद्देश्य परिलक्षित होता है। 29 जुलाई 2023 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुमोदन के तीन वर्ष पूरे हो जाएंगे। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम यह देखें कि क्या इस नीति की दशा और दिशा सही है अथवा कोई बदलाव अभी भी अपेक्षित हैं। आज जब हम पाते हैं कि विभिन्न राज्य सरकारें चिकित्सा और अभियांत्रिकी की पढ़ाई हिन्दी माध्यम से करवाने के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर रही हैं, हम देखते हैं कि इस वर्ष यूपीएससी में हिन्दी मआध्याम ले कर पढ़ रहे छात्रों का सफलता प्रतिशत आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा है तब लगाता है कि धीरे धीरे ही सही प्रयास अपना रंग दिखाने लगे हैं। एक बात यह भी कि पाठ्यपुस्तक स्तर पर भी शोधपरक बदलाव किये जाने चाहिए, बल्कि आमूलचूक पुस्तकों को ही बदल दिए जाने का सही समय है। शिक्षानीति को मुखर होना होगा क्योंकि अभी बहुत लंबा रास्ता तय किया जाना शेष है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है।

लेह-लद्दाख सीमा दर्शन यात्रा

डॉ श्याम नारायण पाण्डेय

एक सुन्दर यात्रा आनंद की प्राप्ति के सर्वोत्तम उपायों में से एक है। यह न सिर्फ तन को तरोताजा करती है बल्कि मन में चल रही अनेक प्रकार की उद्विग्नताओं को भी शांत करती है। इसके द्वारा हमें नए विचारों और नई ऊर्जा से परिपूर्ण नया मन और मस्तिष्क प्राप्त होता है। यदि ऐसी यात्रा में अच्छे यात्रियों का साथ मिल जाए तो यह हमारे जीवन का कायाकल्प कर देती है।

ऐसी ही एक यात्रा सीमा जागरण मंच, दिल्ली प्रान्त के द्वारा आयोजित की गई थी, जिसके अंतर्गत् दिल्ली से लेह–लद्दाख तक की यात्रा शामिल थी। यह यात्रा 9 जून 2023 को प्रातः काल में प्रवासी भवन स्थित सीमा जागरण मंच के दिल्ली प्रान्त के कार्यालय से प्रस्थान करके 18 जून 2023 को प्रातःकाल वापस लौटी।

यात्रा के प्रारंभ होने के अवसर पर सीमा जागरण मंच के राष्ट्रीय सह–संयोजक माननीय मुरलीधर जी, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल विष्णु कांत चतुर्वेदी जी, सीमा जागरण मंच दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल डॉ नितिन कोहली जी, प्रांत के महामंत्री डॉ दीप नारायण पांडेय जी व अन्य गणमान्य लोगों ने उपस्थिति सुनिश्चित करके यात्रियों का उत्साहवर्धन किया व शुभकामनाएं दीं।

नौ दिवसीय इस यात्रा की पहली रात्रि में मनाली में रात्रिवास किया गया। अगली सुबह यात्रा पुनः प्रारंभ हुई परन्तु बरलाचा ला की ओर सायं काल में जाने की स्थिति न होने के कारण यात्रियों ने जिस्पा में रात्रिवास किया और अगले दिन पुनः लेह के लिए यात्रा प्रारंभ की। अगले दिन रात में सभी लेह पहुंचे। इस दिन की यात्रा में पांग की पर्यावरणीय चुनौतियों ने यात्रियों के मनोबल को तोड़ना चाहा परन्तु सबकी मजबूत इच्छाशक्ति ने सभी को सकुशल लेह पहुचने में सहायता की।

अगले दिन की हमारी यात्रा लेह के स्थानीय स्थलों के दर्शन के लिए निकली जिसके अंतर्गत् हमने शांति स्तूप, लेह पैलेस, सिन्धु–जास्कर नदी संगम, मैग्नेटिक हिल, पत्थर साहब गुरुद्वारा और सोनम वांगचुक का विद्यालय जैसे स्थानों का भ्रमण किया। इन सभी स्थानों से लौटने में रात हो गई थी। चूँकि

सीमा जागरण मंच के बिहार प्रान्त के मंत्री अरविन्द जी और अन्य कार्यकर्ताओं ने लेह स्थित भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के 5वीं बटालियन में डिप्टी कमांडेंट गीतिका बौश्या जी और निहाश सुरेश जी से मिलकर भारत माता की प्रति भेट की, साथ ही सीमा सम्बन्धी अनेक विषयों पर चर्चा भी की।

सीमा जागरण मंच के कार्यकर्ता हुंदर स्थिति रेत के टीले (सैंड ड्यून) पर भारत माता की जय के उद्घोष के साथ तिरंगा लहराते हुए।

अगली सुबह पुनः जल्दी निकलना था इसलिए हमने जल्दी सोने का निर्णय लिया।

हमारी अगले दिन की शुरुआत अत्यंत उत्साहजनक थी क्योंकि हमें खारदुंग ला से होकर नुब्रा घाटी जाना था। खारदुंग ला विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा है। बर्फबारी के बीच वहां पर जाना अत्यंत ही रोमांचकारी था। तिरंगा लेकर भारत माता की जय–जयकार कर रहे कार्यकर्ताओं ने वहां का पूरा वातावरण ही परिवर्तित कर दिया।

इसके बाद हमारा अगला पड़ाव नार्थ पुल्लू में रहा, जो यहाँ से आधे घंटे की ही दूरी पर घाटी में स्थित है। यहाँ हमें आर्मी कैंप में सेना के जवानों से मुलाकात हुई जहाँ हमने उन्हें भारत माता का चित्र भेंट किया और कार्यकर्ता बहनों ने उन्हें राखी बांधी। घंटे भर की अत्यंत ही अनौपचारिक वातावरण में हमने कई विषयों पर उनसे बातें कीं, तत्पश्चात् वहां से विदा लिया। आगे नुब्रा वैली की सुन्दरता ने सभी का मन मोह लिया। कुछ घंटों की यात्रा के बाद हम सभी हुंदर पहुंचे, जहाँ तेज हवाओं से बनने वाले बालू के टीले (सैंड ड्यून्स) पर सभी ने आनंददायक क्षण बिताये। वहां पर चल रही तेज हवाओं के कारण हाथ में लहराते तिरंगे अत्यंत मोहक लग रहे थे। हुंदर अपने दुहरे कूबड़ वाले (डबल हम्प्ड) ऊंट के लिए भी प्रसिद्ध है। अनेक यात्रियों ने ऊँटों की सवारी की। वहां की प्रकृति के मनोरम दृश्य का आनंद लिया और वहीं पर कैंप में रात्रिवास किया। रात में कैम्पिंग के दौरान सबने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया।

हुंदर स्थित कैंप में रात्रिवास के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए कार्यकर्तागण

अगली सुबह हमें पाकिस्तान की सीमा पर स्थित तुरतुक गाँव पहुंचना था। सभी यात्री इस गाँव में जाने के लिए अत्यंत उत्साहित थे क्योंकि यह गाँव लद्दाख के उन चार गाँवों में से एक है जो 1971 ई. के पहले पाकिस्तान का हिस्सा था और इस युद्ध के बाद यह भारत के नियंत्रण में आ गया। यहाँ पर हमनें कुछ घंटे स्थानीय लोगों से बातचीत करने व साक्षात्कार तथा सर्वे करने में बिताया। यहाँ के लोगों की सरलता देखते ही बनती है। कृषि और पर्यटन पर आधारित अर्थव्यवस्था वाले इस गाँव के लोगों में एक सामान्य संतुष्टि का भाव देखने को मिलता है।

यहाँ से यात्रा उस ओर प्रस्थान करने वाली थी जो इस यात्रा का सर्वाधिक आकर्षक स्थल था, हम बात कर रहे हैं पांगोंग लेक की जो भारत–तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यह झील लगभग 134 किमी लम्बी है, जिसका लगभग आधा हिस्सा अभी चीन के नियंत्रण में है, 40 प्रतिशत हिस्सा भारत के नियंत्रण में हैं और लगभग 10 प्रतिशत क्षेत्र विवादित है। 700 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैले इस झील की सुन्दरता देखते ही बनती है। ऊँची पहाडियों

खर्दुन्गला से आगे नार्थ पुल्लू, स्थित आर्मी कैंप में सेना के जवानों से मिलकर कार्यकर्ताओं ने उन्हें भारत माता का चित्र देकर सम्मानित किया तथा कार्यकर्ता बहनों ने सेना के जवानों को राखी भी बाँधी। (चित्र में कैप्टन राहुल को भारत माता का चित्र भेंट करते कार्यकर्तागण)

से घिरी हुई यह झील दुनिया की सबसे ऊँची खारे पानी की झील है। यहाँ पर लगातार ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। ठण्ड में यह झील पूरी तरह जम जाती है। यहाँ पर घंटों समय बिताना भी कम लगता है, परन्तु आगे की योजना के कारण हमें यहाँ से शीघ्र ही निकलना पड़ा।

यहाँ के बाद हमने आगे की ओर प्रस्थान किया और चुशूल घाटी के निकट रेजांग ला (Rezang La) में स्थित वॉर मेमोरियल पहुंचे। यह वॉर मेमोरियल मेजर शैतान सिंह की वीरता की गाथा गाता है। यहाँ पहुँचने वाला कोई भी भारतीय राष्ट्रभक्ति के भाव से ओतप्रोत हुए बिना नहीं रह सकता और न ही भारतीय सैनिकों के बलिदान की गाथा सुनकर खुद को भावुक होने से रोक सकता है। वहां पर लहराता गगनचुम्बी तिरंगा देश के दुश्मनों को सन्देश देता है कि जब तक भारतीय सेना की उपस्थिति है कोई दुश्मन देश भारत की तरफ आँख उठाकर नहीं देख सकता है।

यहाँ से हमारी यात्रा लौटने वाली थी, अतः हमने लेह की

लेह स्थित आईटीबीपी अधिकारियों को सीमा संघोष पत्रिका की प्रति भेंट करते हुए

खारदुंग ला में कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। यह विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा है।

तरफ प्रस्थान किया। लेह में हमारी मुलाकात भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के 5वीं बटालियन में डिप्टी कमांडेंट गीतिका बौश्या जी और निहाश सुरेश जी से हुई। हमने उन्हें भारत माता की प्रतिमा भेंट की। लगभग एक घंटे की मुलाकात में हमने सीमा सम्बन्धी अनेक विषयों पर चर्चा भी की, तत्पश्चात् वहां से विदा लेकर सिन्धु भवन पहुंचे और वहीं रात्रि विश्राम किया।

16 जून की सुबह हम लेह से मनाली के लिए निकले और मनाली में रात्रिवास करके अगले दिन सुबह दिल्ली के लिए निकले। अगले दिन यानि 18 जून की सुबह में लगभग 4 बजे सभी यात्री सकुशल दिल्ली पहुँच गये और अपने घरों की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार यह ऐतिहासिक और अविस्मरणीय यात्रा पूर्ण हुई, जो सदैव हमारे मन–मस्तिष्क में अपना स्थान बनाये रहेगी।

भारत माता की जय।

पत्र

बंगाल के पंचायत चुनाव उम्मीदवारों के लिए निर्वासन का जीवन।

पंचायत चुनाव का बिगुल बंगाल में बज गया है, अनेक महिला पुरुष चुनाव नामांकन कर रहे है। बंगाल के चुनाव अक्सर हिंसा की भेंट चढ़ते रहे है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के रूप में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने वाले कई उम्मीदवारों, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, ने उत्तरी कोलकाता के माहेश्वरी सदन में शरण ली है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद से ही उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गईं। जबकि बंगाल में भाजपा नेतृत्व ने अपने उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित घर स्थापित किए हैं, परन्तु बंगाल में अन्य विपक्षी दलों के उम्मीदवारों के लिये स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण है।

सुप्रीम कोर्ट का केंद्रीय सुरक्षा बल को बंगाल में तैनात करने का निर्णय ऐसे उम्मीदवारों की सुरक्षा हेतु था। आज के बंगाल में गैर टीएमसी समर्थक होना आवाजहीन होना है। बंगाल के नेता दक्षिणपंथी मतदाताओं से वोट तो चाहते हैं लेकिन चोरी–छिपे। लगातार राजनैतिक हत्याओं पर राजनीतिक विरोध का अभाव भयावह है। ऐसी हत्याओं की खबरों को या तो नजरअंदाज कर दिया जाता है या अखबारों के अंदर के पन्नों पर कुछ वाक्यों तक ही सीमित कर दिया जाता है। बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद गैर टीएमसी समर्थकों के खिलाफ अपराध में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। आज बंगाल में दक्षिणपंथी समर्थक होने का मतलब सोशल मीडिया, राजनीतिक हलकों और वास्तविक जीवन में नफरत के दैनिक उत्पीड़न के साथ सुबह जागना है। उनके अस्तित्व पर हमले लगातार जारी हैं। इसमें दुर्गा पूजा पंडालों रामनवमी जुलूसों और हनुमान जयंती समारोहों पर होने वाले वार्षिक हमलों को जोड़ दें, तो हमारे पास बंगाल के संकटग्रस्त, घायल, भयभीत और परित्यक्त समुदाय की एक तस्वीर है।

– परमवीर 'केसरी', मेरठ

सीमा जागरण मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम 'सीमा संवाद'

आशीष शिशौदिया

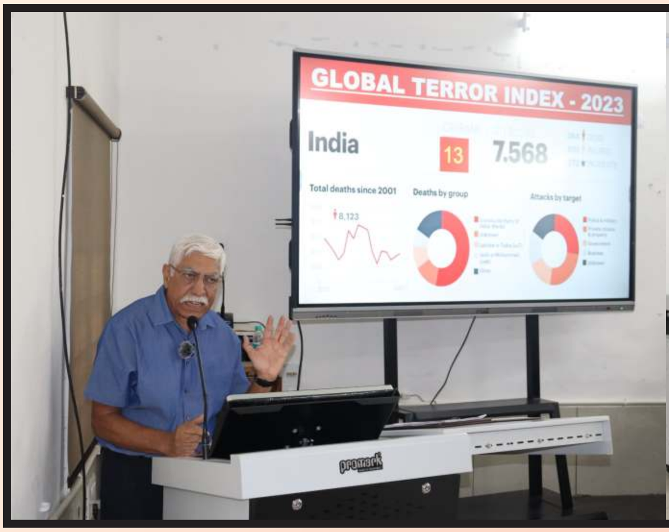

दिल्ली : सीमा जागरण मंच दिल्ली प्रान्त द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय में दिनांक 18 जून 2023, को 'सीमा संवाद' परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 'सीमा संवाद' परिचर्चा दिल्ली विश्विद्यालय के 'Modern Indian Languages and Literary Studies Department' के साथ सयुंक्त रूप से 'आतंकवाद और भारत के संदर्भ में आतंकवाद का मुकाबला' (Terrorism and Counter Terrorism in Context of India) विषय पर था।

'सीमा संवाद' के कार्यक्रम में वर्तमान समय में मौजूद आतंकवादी गतिविधियों पर गंभीर रूप से विचार विमर्श करते हुए कई महत्वपूर्ण विषयों पर दृष्टि डाली। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कई ऐसे मुद्दों पर भी बात की, जिससे भारत आतंकवाद का मुकाबला कर सके। केवल मुकाबला ही न कर सके बल्कि आंतकवादी हमलों से अपनी सुरक्षा भी करने में विजय प्राप्ति करे।

दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट फैकेलिटी में आयोजित इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने भारत पर पूर्व हुए आतंकी हमलों पर भी बात की और बताया कि किन परिस्थितियों में भारत पर हमले हुए हैं। हमले होने के कई कारणों की चर्चा भी इस कार्यक्रम में की गई।

आतंकवाद और भारत के संदर्भ में आतंकवाद का मुकाबला' की इस 'सीमा संवाद' परिचर्चा के मुख्य वक्ता ले. जनरल रिटायर विनोद भाटिया जी रहे। वहीं इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी, दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्य विभागों के प्राध्यापक भी भरी संख्या में शामिल हुए।

कार्यक्रम का सफलता पूर्वक आयोजन किया गया। जिसमे सीमा जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक श्रीमान मुरलीधर जी, प्रांत महामंत्री डॉ. दीपनारायण पांडेय और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

डॉ. निहार रंजन नायक के द्वारा

“चीन के नये पर्यटक दिशानिर्देश: कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए निहितार्थ” विषय पर एक आंतरिक सीमा संगोष्ठी का आयोजन, 10 जून 2023, प्रवासी भवन

भारतीय सीमा अध्ययन संस्थान के द्वारा दिनांक 10 जून 2023 को प्रवासी भवन में "चीन के नये पर्यटक दिशानिर्देश: कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए निहितार्थ" विषय पर एक आंतरिक सीमा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता डॉ. निहार रंजन नायक थे जोकि मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान में रिसर्च फेलो के पद पर कार्यरत है। वक्ता ने संगोष्ठी की शुरुआत विषय की परिचय के साथ की तथा रेखांकित किया किस तरह कैसे मेंसर जोकि चुसुल संधि के अनुसार लद्दाख का हिस्सा को कूटनीतिक रूप से भारत ने आज तक चीन के साथ नही उठाया। इसके बाद डॉ नायक ने मानसरोवर यात्रा की हिन्दू, बौद्ध तथा जैन धर्म में महत्व को रेखांकित किया और कहा कि इस वर्ष चीन ने भारत की तरह मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा पर जाने से रोकने के लिए नये पर्यटक दिशानिर्देश निकाले है जिसका सीधा असर भी दिखाई दे रहा है। विषय को स्पष्टता से समझाने के लिए डॉ नायक ने नये पर्यटक दिशानिर्देश की प्रति सभी के साथ साझा भी की।

क्योंकि नेपाल के लिए मानसरोवर की यात्रा व्यापक स्तर पर व्यवसाय पैदा करती है इसलिए डॉ नायक ने चीन के नये पर्यटक दिशानिर्देशों के नेपाल की ट्रेवल इंडस्ट्री पर होने वाले प्रभाव को भी रेखांकित किया। डॉ नायक के अनुसार चीन के नये पर्यटक दिशानिर्देशों ने व्यापक नकरात्मक प्रभाव नेपाल की ट्रेवल इंडस्ट्री पर डाला है। आगे चल कर उन्होंने कहा की चीन के नये पर्यटक दिशानिर्देश का उदेश्य वास्तव में भारतीय नागरिकों को मानसरोवर की यात्रा के लिए हतोऊत्साहित करना है। जिसको ध्यान में रखकर चीन ने भारतीय नागरिकों को ऑनलाइन वीसा व्यवस्था को बंद कर फिजिकल सिस्टम से वीसा देना शुरू किया है जिसका उदेश्य भारतीय नागरिकों का मानसिक शोषण करना है। इस सन्दर्भ में चीन सफल भी हुआ है क्योंकि इस बार यात्रा के रुझान अच्छे नहीं रहे है।

डॉ नायक के अनुसार चीन ऐसा करके भारतीय जनता तथा सरकार के बीच यह मिथ स्थापित करना चाहता है कि भारत सरकार की गलवान के ऊपर पोजीशन की वजह से मानसरोवर यात्रा प्रभावित हो रही है। भारत का अमेरिका की तरफ बढ़ता झुकाव भी चीन की इस निति का एक कारण हो सकता है।इसके बाद डॉ नायक ने मानसरोवर जाने वाले तीन मुख्य रास्तों तथा उनकी कॉस्ट का पावर पॉइंट (PPT) के माध्यम से विस्तृत विवेचन किया। इसके बाद डॉ नायक ने नये पर्यटक दिशानिर्देशों के मुख्य बिन्दुओं से सब को अवगत कराया तथा क्या–क्या बदलाव इस बार किये गए है उसकी विस्तृत व्याख्या की।

इसके बाद डॉ नायक ने डाटा के माध्यम से यात्रा में घटते व बढ़ते कारणों की व्याख्या की। उनके अनुसार 2018 बड़ी संख्या में भारतीय लोगों ने मानसरोवर की यात्रा की जिसका एक मुख्य कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दर्शनार्थियों को कई तरीके की सुविधायें प्रदान करना था।

यदि बात कारणों की करें तो डॉ नायक के अनुसार भारत– अमेरिका की बढ़ती घनिष्टता, भारत का बार्डर रोड इनिशटिव (BRI) आलोचना तथा भारत का नेपाल में चीन के बिजली प्रोजेक्ट्स से इलेक्ट्रीसिटी न खरीदना कुछ मुख्य कारण है। भारत की तरफ से इस विषय पर कूटनीतिक रूप से कोई चर्चा नहीं हुई है जोकि एक चिंताजनक विषय है। संगोष्ठी का एक समापन ज्ञानवर्धक प्रश्न–उत्तर सेशन के साथ हुआ।

वन्दे मातरम्

कार्यशाला की कार्यवाही

- डॉ. विजय कुमार चौधरी

SJM, SRKPS & SAFE के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित

"मंथन - 2023 कार्यक्रम - एनजीओ की भूमिका"

दिनांक - 11 जून 2023

स्थान - रैडिसन ब्लू होटल, कौशांबी, गाजियाबाद

सुरक्षित सीमा - समर्थ भारत

जुलाई, 2023

1.0 कार्यक्रम के मुख्य बिंदु

राष्ट्रव्यापी स्तर पर सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए कार्य करने वाले गैर-सरकारी, गैर राजनीतिक संस्था सीमा जागरण मंच, SRKPS & SAFE ने रविवार, दिनांक - 11 जून 2023 को "सीमा क्षेत्र का एकीकृत विकास में एनजीओ की भूमिका" विषय पर **मंथन 2023 कार्यक्रम** का आयोजन किया। ("Manthan-2023" An Integrated Development of Border Area - Role of NGOs) कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी रहे। जिन्होंने मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

कार्यक्रम के मुख्य बिंदु इस प्रकार है:-

- **मंथन-2023 के आयोजक मंडल**
    - श्री मुरलीधर भिंडा जी, अखिल भारतीय सह संयोजक, सीमा जागरण मंच
    - श्री नितिन कोहली जी, अध्यक्ष, सीमा जागरण मंच, दिल्ली
    - CA (डॉ.) विजय चौधरी जी, सेवा प्रमुख, सीमा जागरण मंच
    - डॉ. अमित कुमार अग्रवाल जी, संयोजक मंथन कार्यशाला
    - डॉ. सौहार्द सिंह जी
    - श्री आलोक अग्रवाल जी
    - एडवोकेट श्रीमति ऋतु रस्तोगी
- **मंथन 2023 - कार्यक्रम में 4 सत्र हुए**
    - प्रथम सत्र- **Overview of Indian Borders : Challenges Role of NGOs** : Panel Discussion
        - Moderator: Dr. Sauhard Singh
        - Infrastructure at Border: Shri Sanjay Agarwal
        - Costal Border: Shri Hamendra Rajput
        - Land Border: Dr. Jatin Kumar
        - Concluding Remarks: Dr. Shreesh K Pathak

2

वन्दे मातरम्

- दूसरा सत्र- **Enabling CSR Guidelines for Integrated Development of Borders**
  - Session Chairman: Shri Raja Iqbal Singh
  - Dr. Amit Kumar Agrawal
- तीसरा सत्र- **Raising Funds on Social Stock Exchange**
  - CA. Kuldeep Kothari
- चौथा सत्र- **Presentation of shortlisted NGO's in front of CSR heads of following PSU's**
  - Shri ML Meena, GM Finance & Head CSR, REC
  - CA. Mahesh Sharma, GM Finance NHPC
  - Shri K Ganeshiya, CGM-HR, NBCC
  - Shri Anjeev Kumar Jain, GM Finance, RITES
  - Shri Viney Sethi, AGM, NTPC Ltd.
  - Shri Gurtej Singh, IOC
  - Gyaneshwar Prasad Payasi, CGM Power GRID

- **कुल प्रतिभागी - 300**
  - कार्यक्रम में भाग लेने वाले एनजीओ की कुल संख्या - **67** (कुल व्यक्तिगत संख्या - **150**). एनजीओ का विवरण इस प्रकार है:
    - दिल्ली एनसीआर से आए एनजीओ की संख्या – **34** (दिल्ली, नोएडा, वसुंधरा, वैशाली, गुरुग्राम)
    - दिल्ली राज्य के बाहर से आए एनजीओ की संख्या – **33**
    - दक्षिण भारत से – **1**
    - पूर्व भारत से – **3**
    - पश्चिम भारत से – **15**
    - उत्तर भारत से – **28**
    - मध्य भारत से – **1** (मध्य प्रदेश)
  - अलग-अलग राज्यों के एनजीओ की संख्या - **63**

3

- आयोजन में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या - **150**
- मंथन-**2023** में भाग लेने वाले एनजीओ की सूची संलग्न है **(Annexure-1)**

- Sponsor of **मंथन**-2023: **NHPC Ltd.**

2.0 NGO - द्वारा बताए गये विषय, उनकी आवश्यकता - अन्त में क्या?

- **Doers Foundation - Himachal Pradesh**
    - यह संस्था हिमाचल प्रदेश में काम करती है। सीमावर्ती क्षेत्र में क्रॉस बॉर्डर की बहुत बड़ी समस्या है। आपराधिक गतिविधिभी ज्यादातर सीमावर्ती क्षेत्र में होती है।
    - सीमावर्ती क्षेत्र में हमने देखा है कि बहुत से परिवार सीमा पार (क्रॉस बॉर्डर क्षेत्र में) जाकर आपराधिक गतिविधि करते हैं क्योंकि वहां पर सामाजिक लाभार्थी योजनाएँ बहुत कम हैं । सीमावर्ती क्षेत्र के अधिकांश लोग खेतिहर मजदूर हैं अथवा देश के अन्य भागों में प्रवास करते हैं।
    - हमें लगता है कि वहां पर पर्यटन (टूरिज्म) का विकल्प बहुत अच्छा है, इससे आजीविका के अन्य विकल्पों पर निर्भरता कम हो जाएगी। अगर ये पर्यटन क्षेत्र (टूरिस्ट एरिया) के रूप में विकसित हो जायेंगे तो वहां के लोगों को रोजगार के साधन मिल जायेंगे। अगर हम बड़ी संख्या में वहां के लोगों के लिए रोजगार के संसाधन उपलब्ध करते हैं तो आपराधिक गतिविधि काफी कम हो जायेगी।

- **Deerghayu Himalayan Organics - Uttrakhand**

- सीमावर्ती क्षेत्र से हमारा एक करीबी रिश्ता है । आज के समय में सीमावर्ती क्षेत्रों में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है | सरकार यह चाहती है कि सीमावर्ती क्षेत्रों के गांव खाली नहीं रहने चाहिए क्योंकि इस कारण से पड़ोसी देशों को सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों में कब्जा करने का मौका मिल जाता है । इससे हमारी जमीनी सीमाएं कम हो रही हैं । वहा के लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है वहां के लोग अपने गांव को छोड़कर शहर में काम करने के लिए चले जाते हैं, जिस कारण वहां के गांव खाली हो जाते हैं |
- हमें वहां पर संसाधन के ऐसे स्रोत विकसित करने चाहिए, जिससे वहां के लोगो को आजीविका का साधन मिल जाए ताकि वहां के लोग अपने गांव छोड़कर ना जाएँ। इसके लिए हमारे संगठन ने एक कदम उठाया है कि वहां पर बागवानी और खेती बाड़ी जीविका के साधन बनाए जाए । टूरिज्म से भी वहां के लोगों के लिए जीविका का एक अच्छा साधन उपलब्ध हो जाता है |
- हमारे प्रयास से अगर हम वहां की बुनियादी संरचना को ठीक करें तो वहां का व्यक्ति गांव छोड़कर शहर नहीं जाएगा और वहां के गांव खाली नही होंगे।

- **Param Jyoti Sewa Foundation - West Bengal**
  - पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र में बाल-विवाह बहुत बड़ी समस्या है जो कि महिलाओं में एनीमिया जैसी समस्याओं को बढ़ावा देता है | इसके अतिरिक्त बच्चो में कुपोषण की समस्या भी विकराल है । एक अन्य बड़ा मुद्दा वहां का गैर कानूनी व्यापार जैसे कि बीड़ी बनाना । **24** परगना, मुर्शिदाबाद जैसे क्षेत्र में बाल मजदूर बहुत

बड़ी संख्या में हैं। वहां पर स्वास्थ्य का मुद्दा एक गंभीर समस्या का रूप धारण किये हुए है । इसके अतिरिक्त मुर्शिदाबाद में मानव तस्करी भी व्यापक रूप में होती है । वहां पर सामाजिक कुरीतियों के कारण भी महिला और बच्चो में यह प्रवृत्ति देखी गई है । वहां के लोग नहीं चाहते कि तस्करी ख़त्म हो क्योंकि वहां पर रोजगार के उचित साधन नहीं हैं । वहां के लोगो की बीएसएफ जवानों के साथ संवाद भी बहुत कम है ।वहां पर मानव तस्करी करके बच्चों को दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई जैसे बड़े शहरों में काम करवाने के लिए लाया जाता है । उनके आजीविका के साधनों में बदलाब करना भी बहुत जरूरी है। साथ ही वहां पर रोजगार के उचित अवसर उपलब्ध कराकर भी इसे ख़त्म किया जा सकता है ।

- **PAIGAM - People's Association in Grassroots Action and Movements**
  - यह संस्था सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। वहां पर जब हमने धार्मिक अर्थव्यवस्था पर काम किया तो पता चला कि सीमावर्ती क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हैं । अतः सीमा जागरण मंच को भारत के सीमावर्ती क्षेत्र के विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए।

- **Transform Foundation**
  - अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को पढ़ाकर उनके सपनों को साकार करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि मुंबई, दिल्ली में रहने वाले बच्चों की तुलना सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों से की जाए तो

6

सीमावर्ती क्षेत्रों का बच्चा दिल्ली, मुंबई के बच्चों से आगे निकल जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्रों के बच्चे को यदि आपने सपना दिखा दिया तो वह लैंप के नीचे पढ़कर उस सपने को पूरा करना जानता है। सीमावर्ती क्षेत्रों के बच्चों को आगे बढ़ाना ही हमारा लक्ष्य है।

3.0 सीमा जागरण मंच की मांग

- "Manthan-2023" कार्यक्रम की शुरुआत में सीमा जागरण मंच के दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष नितिन कोहली जी ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने कहा कि आज सीमावर्ती क्षेत्रों में सबसे बड़ी चुनौती घुसपैठ, मादक पदार्थों की तस्करी और धर्मांतरण से जुड़ी हुई हैं। इसके पीछे कारण है सीमावती क्षेत्रों में संसाधनों की कमी और वहां के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होना। देश विरोधी तत्व रुपयों का लालच देकर सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मासूम लोगों को धोखा देते हैं। हमें ऐसे ही देश विरोधी तत्वों के खिलाफ लड़ना है और उन्हें रोकना है। सीमा जागरण मंच निरंतर ऐसी गतिविधियों की रोकथाम के लिए कार्य करने में जुटा हुआ है। सीमा जागरण मंच सीमावर्ती क्षेत्रों में शिक्षा केन्द्रों को संचालित करता है, स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियां करता है जैसे कि उन क्षेत्रों में एंबुलेंस की व्यस्था करना इत्यादि ।
- आज सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की आवाज़ जन-जन तक पहुंचे, इसके लिए जन-जागरण की अत्यधिक आवश्यकता है। समाज के हर वर्ग को सीमावर्ती क्षेत्रों के हितों की रक्षा के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जब हम एक साथ काम करेंगे तभी तो होगा-'सुरक्षित सीमा समर्थ भारत'।

4.0 माननीय मुख्य अतिथि अर्जुन राम मेघवाल जी की टिप्पणी - 'मंथन' 2023

- सीमा जागरण मंच ने एक मंथन किया देशभर के सारे **NGO**, **PSU** जो कि **CSR** के तहत अपने प्रॉफिट का 2% खर्च करते हैंअगर वो

7

बॉर्डर एरिया पर भी खर्च करें तो भारत की सीमावर्ती क्षेत्र के विकास की ओर गति मिलेगी । ये सीमा जागरण मंच का बहुत ही अच्छा प्रयास है और बहुत सारे एनजीओ संगठन भी आए हैं ।

- इस संयुक्त प्रयास के बाद सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिकों के जीवन में एक अच्छा सुधार आयेगा । सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए वहां की अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) को मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। वहां पर स्कूल में कोई भी नवाचार (**Innovation**) हो, सड़कों की स्थिति में सुधार का विषय हो अथवा किसी कंप्यूटर लैब की आवश्यकता हो। इन सब आवश्यकताओं का इसके माध्यम से समाधान होगा ।
- सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन, सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन, जनसांख्यिकीय बदलाव पर शोध, खतरों और उपायों, बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि विकास और पर्यावरणीय चुनौतियों जैसे बिंदुओं पर गहनता से चर्चा की गई और इस पर समन्वयक रूप से कार्य करने की योजना बनी।
- एक सुझाव जो आया है कि कंपनी एक्ट के सेक्शन **135 (A)** में जो सीएसआर का शेड्यूल है उसमें जो **12** आइटम हैं, उनमें बॉर्डर एरिया में काम करने वाली गतिविधि को जोड़ने का सुझाव आज के मंथन से निकल रहा है ।
- सीमा जागरण मंच द्वारा मंथन कार्यक्रम का आयोजन करना एक अच्छी पहल है । इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में जो समस्याएं है, उनको दूर करने में सहायता मिलेगी।

5.0 श्री मुरलीधर भिंडा जी का भाषण

- हमारे सभी गैर सरकारी संगठन (**NGOs**) सामाजिक विकास के लिए काम करते हैं, सभी के मन में सामाजिक संवेदना है,जितने भी फंड देने वाले सीएसआर हैं वे भी देश के विकास के लिए सदैव तत्पर हैं । जितने भी **NGOs** आए हैं सभी अच्छा काम कर रहे हैं । हमने सभी

NGOs की कार्यप्रणाली को काफी अच्छे से सुना है । **NGOs** ने कहा कि भारत में **31** लाख **NGOs** रजिस्टर है भारत सरकार का **NGOs** को लेकर जो भी मानदंड (नॉर्म्स) हैं, हम सभी उनका पालन करें। आप लोगों के माध्यम से ऐसा कहा गया है कि सीएसआर फंड का कुछ प्रतिशत सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार को कानून में लाना चाहिए । यदि आप लोग ऐसा बोलते हैं तो इस सन्दर्भ में आप सभी को एक प्रस्ताव लाना चाहिए | यहाँ पर उपस्थित सभी **NGOs** का लिखित में उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होना चाहिए । सीमा जागरण मंच और आप सभी के प्रयास से इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार पर बार-बार स्मरण करते रहना होगा |

- आज के समय में वास्तविक सूचनाओं का अभाव है, जिस कारण से समस्या के निदान करने वाले लोग जमीनी हकीकत से अपरिचित हैं । अतः नीचे की जानकारी संग्रहित करना अनिवार्य है । हम सभी गई सरकारी संगठनों का उद्देश्य एक ही है, अतः सभी को अपने संगठन के नाम को बरकरार रखना है ।
- भारत के प्रत्येक नागरिक हमारे लिए भगवान है, चाहे वह किसी भी जाती, धर्म, भाषा या क्षेत्र का हो, हमें प्रत्येक नागरिक के लिए काम करना चाहिए और प्रत्येक नागरिक का सहयोग लेना चाहिए । अतः सभी सीमावर्ती नागरिकों का साथ देना चाहिए, परन्तु साथ ही हमें राष्ट्रविरोधी गतिविधि करने वाले लोगों से भी सावधान रहकर राष्ट्र की सुरक्षा करनी चाहिए । इसीलिए हम सभी को राष्ट्र की सुरक्षा हेतु सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए हमें बॉर्डर के विकास पर काम करना चाहिए । हमें सीमावर्ती क्षेत्रों में जागरूकता एवं विकास के लिए भी कुछ अध्ययन करना चाहिए । इसीलिए कुछ **NGOs** अध्ययन करेंगे और जो समस्या सामने आएगी उसी समस्या के आधार पर कुछ **NGOs** वहां पर काम करेंगे और कुछ **CSR** हमारे संसाधनों में सहयोग करेंगेऔर कुछ समाज के लिए कार्य करेंगे ।

- अभी हमें व्यवस्थित रूप से समाज के अंदर और सरकार से यानी की जो भी **CSR** देने वाली कंपनी है उनसे सहयोग लेने के लिए उनका अध्ययन जरूरी है और जो भी जमीनी समस्या है उनका अध्ययन करना भी जरूरी है । इस समाधान के लिए कुछ विषय निकालना है और सभी ईमानदारी से काम करेंगे । इसी विश्वास के साथ हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए और सुरक्षा के लिए काम करेंगे ।
- सीमा जागरण मंच एक प्रयास करने वाली गैर सरकारी और गैर राजनीतिक संगठन है । इसीलिए हम सभी मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर विकास योजना को साझा करेंगे । और इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आप सभी के प्रयास से भारत की सीमाएं विकसित होंगी ।

6.0 SJM, SRKPS SAFE & NGOs के संयुक्त तत्वधान के अंतिम निष्कर्ष

- अनुच्छेद **135** के तहत पीएसयू और सीएसआर को सामाजिक और पर्यावरण से जुड़े व्यापार का सञ्चालन (बिजनेस ऑपरेशन) और परस्पर क्रिया (इंटरेक्शन) करनी चाहिए । हम सब यह चाहते हैं कि सरकार इस विषय पर गहन चर्चा करे ।
- एलटीसी जो कि सरकारी कर्मचारियों को **2** साल में एक बार मिलती है हम सब यह चाहते हैं कि सरकार अतिरिक्त एलटीसी में सीमा क्षेत्र को अनिवार्य करे और जब भी अतिरिक्त एलटीसी मिले उसमें हर बार अलग-अलग सीमावर्ती क्षेत्र सम्मिलित हो ।
- सीमावर्ती क्षेत्र में जीवंत गांव का विकास - केंद्र सरकार पड़ोसी देशों से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए सीमित कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे वाले सीमावर्ती गांवों का विकास करे। गाँवों को प्राथमिकता के आधार पर सड़क, बिजली, पानी और इंटरनेट

जैसी सुविधाओं से जोड़ने के साथ-साथ मौसम से जुड़ी समस्याओं से निपटने हेतु भी तैयार किया जाएगा।

- भारत सरकार द्वारा आयोजित होने वाले कॉन्फ्रेंस को बॉर्डर क्षेत्र में आयोजन को प्राथमिकता दी जाए।
- सीमा जागरण मंच की जो अंतिम सिफारिश यह है कि सीएसआर का एक निश्चित हिस्सा सीमावर्ती क्षेत्रों में लगाया जाय | इसका विवरण निम्नवत है- हर कॉर्पोरेट पीएसयू को अपने लाभ का **2%** सीएसआर में खर्चा करना होता है| इस हिसाब से यदि सरकारी और अर्ध-सरकारी पीएसयू की बात करें तो लगभग **15000** करोड़ रूपए के आस-पास इकठ्ठा हो जाता है । ऐसे ही निजी क्षेत्र से लगभग **15000** करोड़ रुपये इकट्ठा हो जाता है । मान लीजिए इसमें से हम अनुच्छेद **135** के तहत भारत के सारे बॉर्डर कवर करें और सीएसआर का कुछ ही प्रतिशत फंड मिल जाए, यानि कि सरकारी और अर्ध-सरकारी पीएसयू के **15000** करोड़ का **2%** फंड भी मिल जाए लगभग **300** करोड़ का फंड इकठ्ठा हो जाता है, जिससे हमारे सीमावर्ती क्षेत्र का अच्छे से विकास हो सकता है । इस फण्ड से हमारी **15000** किमी लम्बी जमीनी सीमा का और **7000** किमी लम्बी समुंद्री सीमा का आसानी से विकास सकता है ।

----------x-----------x---------------x------------x---------

वन्दे मातरम्

Annexure-2

मंथन 2023 कार्यक्रम की कुछ झलकियां

मंत्री जी दीप प्रज्वलित करते हुए

CA (Dr.) विजय चौधरी जी सभा को सम्बोधित करते हुए

आदरणीय श्री मुरलीधर भिंडा जी, मंथन 2023 कार्यक्रम में भाषण देते हुए

मंत्री जी मंथन 2023 कार्यक्रम में भाषण देते हुए

अमित कुमार अग्रवाल जी सभा को सम्बोधित करते हुए

मंत्री जी के साथ डॉ. सौहार्द सिंह जी सीमा जागरण मंच, सेवा विभाग में कार्यकर्ता

मंथन 2023 कार्यक्रम का विभिन्न समाचार पत्रों में कवरेज

दैनिक पैनी खबर

वर्ष - 15, अंक - 73, पृष्ठ-8, रविवार, 11 जून 2023, मूल्य 2 रु० www.painikhabar.online पृष्ठ-8: लाइव सीसीटीवी सर्विलांस...

राष्ट्रव्यापी स्तर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में लिए कार्य करने वाली गैर-सरकारी संगठन सीमा जागरण मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम

गाजियाबाद, पैनी खबर, ब्यूरो। राष्ट्रव्यापी स्तर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में लिए कार्य करने वाली गैर-सरकारी संगठन सीमा जागरण मंच ने दिनांक 11 जून 2023 (रविवार) को गाजियाबाद के कौशांबी स्थित रेडिसन ब्लू होटल में सीमा क्षेत्र का एकीकृत विकास - एनजीओ की भूमिका विषय पर मंथन 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें 150 से अधिक एनजीओ के प्रतिनिधियों समेत 300 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी रहे जिन्होंने मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत में सीमा जागरण मंच के दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली जी ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने कहा कि आज सीमावर्ती क्षेत्रों में सबसे बड़ी चुनौती घुसपैठ, मादक पदार्थों की तस्करी और धर्मांतरण से जुडी हुई हैं। इसके पीछे कारण है सीमावर्ती क्षेत्रों में संसाधनों की कमी और वहां के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होना। देश विरोधी तत्व रुपयों का लालच देकर सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मासूम लोगों को धोखा देते हैं। हमें ऐसे ही देश विरोधी तत्वों के खिलाफ लड़ना है और उन्हें रोकना है। सीमा जागरण मंच निरंतर ऐसी गतिविधियों की रोकथाम के लिए कार्य करने में जुटा हुआ है। सीमा जागरण मंच सीमावर्ती क्षेत्रों में शिक्षा केन्द्रों को संचालित करता है, स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियां करता है जैसे उन क्षेत्रों में कई एंबुलेंस की व्यस्था करना इत्यादि। आज सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की आवाज जन-जन तक पहुंचे के लिए जन जागरण की अत्यधिक आवश्यकता है। समाज के हर वर्ग सीमावर्ती क्षेत्रों के हितों की रक्षा के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जब हम एक साथ काम करेंगे तभी तो होगा सुरक्षित सीमा समर्थ भारत।

इसके बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर दूरगामी सोच है, उनका कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना बेहद जरूरी है। कानून मंत्रियों कहा कि जम्मू कश्मीर में जो समस्याएं थी उसकी देन स्वतंत्रता के पश्चात शासन करने वाले लोग थे। उस दौरान की सरकारों ने जम्मू कश्मीर को पहाड़ी क्षेत्र बताकर वहां का विकास करने में रुचि नहीं दिखाई, जम्मू कश्मीर की बजाय अन्य राज्यों के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया गया। जब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू था उस दौरान वहां के लोग खुद को आतंकियों के चलते खुद को असुरक्षित महसूस करते थे लेकिन आज अनुच्छेद 370 हटने के बाद इस सीमावर्ती राज्य के लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। वहां आतंकवाद न के बराबर है। सीमा जागरण मंच द्वारा मंथन कार्यक्रम का आयोजन करना एक अच्छी पहल है जिससे समाज में सीमावर्ती क्षेत्रों में जो समस्याएं है जो उसको दूर करने में सहायक होंगी।

कानून मंत्री ने कहा सीमावर्ती क्षेत्र प्राकृतिक रूप से भी काफी सुंदर हैं चाहे जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो या पूर्वोत्तर भारत के राज्य। हमें सीमावर्ती राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। कई राज्यों में ऐसे अद्भुत जगह हैं जिसकी सुंदरता आपको मोहित कर देगी। सीमा जागरण मंच इसी से सम्बंधित एक अनूठा कार्य कर रहा है जिसके लिए संगठन प्रशंसनीय योग्य है। सीमा जागरण मंच वर्ष में 2-3 बार सीमा दर्शन यात्रा के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को सीमावर्ती क्षेत्रों में यात्रा करवाते हैं जिससे वहां की परिस्थिति का बोध हो सके और वहां पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। समाज के अन्य लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने में अपना योगदान देना चाहिए। कार्यक्रम में कई अलग-अलग सत्र आयोजित किए गए जिसमें प्रमुख रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन, सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन, जनसांख्यिकीय बदलाव पर शोध, खतरों और उपायों, बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि विकास और पर्यावरणीय चुनौतियों जैसे बिंदुओं पर गहनता से चर्चा की गई और इस पर समन्वयक रूप से कार्य करने की योजना बनी। इसके अलावा कई एनजीओ के प्रतिनिधियों ने सीमा जागरण मंच के मंथन 2023 के जरिए विभिन्न पब्लिक सेक्टर यूनिट के सीएसआर प्रमुखों के सामने प्रस्तुतिकरण देकर आपसी समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया।

सीमा जागरण मंच की मंथन के जरिए सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई यह पहल निश्चित रूप से उन चुनौतियों में उभरती चुनौतियों की पहचान करने और समाधान प्राप्त करने में मदद करेगी जो वे सीमा क्षेत्र के विकास के लिए अपनी कार्य योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं।

अनुच्छेद 370 हटने पर कश्मीर के लोग सुरक्षित : मेघवाल

कौशांबी मे 'सीमा क्षेत्र का एकीकृत विकास, एनजीओ की भूमिका' कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (पगड़ी पहने हुए) को सम्मानित करते संस्था के पदाधिकारी • सौ. एनजीओ

वि. साहिबाबाद : कौशांबी के रेडिशन ब्लू होटल में रविवार को सीमा जागरण मंच संगठन की ओर से 'सीमा क्षेत्र का एकीकृत विकास व एनजीओ की भूमिका' विषय पर 'मंथन 2023' कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें 150 एनजीओ के 300 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रहे। कार्यक्रम में सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा व विकास पर मंथन हुआ।

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए वहां का इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना बेहद जरूरी है। स्वतंत्रता के बाद शासन करने वाले लोगों की वजह से जम्मू-कश्मीर में समस्याएं थीं। जम्मू-कश्मीर को पहाड़ी क्षेत्र बताकर विकास नहीं किया गया। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू होने पर यहां के लोग खुद को आतंकियों से असुरक्षित महसूस करते थे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद सीमावर्ती राज्य के लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। अब आतंकवाद न के बराबर है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख व पूर्वोत्तर राज्य प्राकृतिक रूप से संपन्न हैं। यहां पर्यटन को बढ़ावा देना है।

सीमा जागरण मंच संगठन दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली ने कहा कि आज सीमावर्ती क्षेत्रों में सबसे बड़ी चुनौती घुसपैठ, मादक पदार्थों की तस्करी व धर्मांतरण है। देशविरोधी तत्व रुपयों का लालच देकर सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मासूम लोगों को धोखा देते हैं। देशविरोधी तत्वों के खिलाफ लड़ना है। उनका संगठन सीमावर्ती क्षेत्रों में शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्र में पलायन, पर्यटन, जनसांख्यिकीय बदलाव, बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि विकास और पर्यावरण आदि पर मंथन हुआ।

02 Ghaziabad

गाजियाबाद, सोमवार, 12 जून-2023 | दैनिक जर्नी ऑफ सक्सेस

सीमा जागरण मंच ने किया 'मंथन' का आयोजन

सीमा क्षेत्र का एकीकृत विकास - एनजीओ की भूमिका विषय पर हुई वार्ता

सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए जुटे स्वयंसेवी

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : राष्ट्रव्यापी स्तर पर सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए कार्य करने वाली गैर-सरकारी संगठन 'सीमा जागरण मंच' ने रविवार को सीमा क्षेत्र का एकीकृत विकास एनजीओ की भूमिका विषय पर मंथन 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसमें 150 से अधिक एनजीओ के प्रतिनिधियों समेत 300 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय कानून मंत्री रहे। जिन्होंने मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत में सीमा जागरण मंच के दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने कहा कि आज सीमावर्ती क्षेत्रों में सबसे बड़ी चुनौती घुसपैठ, मादक पदार्थों की तस्करी और धर्मांतरण से जुड़ी हुई हैं। इसके पीछे कारण है सीमावर्ती क्षेत्रों में संसाधनों की कमी और वहां के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होना। देश विरोधी तत्व रुपयों का लालच देकर सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मासूम लोगों को धोखा देते हैं। हमें ऐसे ही देश विरोधी तत्वों के खिलाफ लड़ना है और उन्हें रोकना है। सीमा जागरण मंच निरंतर ऐसी गतिविधियों की रोकथाम के लिए कार्य करने में जुटा हुआ है। सीमा जागरण मंच सीमावर्ती क्षेत्रों में शिक्षा केन्द्रों को संचालित करता है, स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियां करता है जैसे उन क्षेत्रों में कई एंबुलेंस की व्यस्था करना इत्यादि।

'Integrated Development of Border Areas - Role of NGOs'

Ashok Sharma
info@impressivetimes.com

SEEMA JAGRAN MANCH, A NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION WORKING IN THE BORDER AREAS NATIONWIDE, ORGANIZED 'MANTHAN 2023' ON 11TH JUNE 2023 (SUNDAY) AT RADISSON BLU HOTEL, KAUSHAMBI, GHAZIABAD ON THE TOPIC 'INTEGRATED DEVELOPMENT OF BORDER AREAS - ROLE OF NGOS'

NEW DELHI : Seema Jagran Manch, a non-governmental organization working in the border areas nationwide, organized 'Manthan 2023' on 11th June 2023 (Sunday) at Radisson Blu Hotel, Kaushambi, Ghaziabad on the topic 'Integrated Development of Border Areas - Role of NGOs'. Organized the event in which more than 300 people including representatives of more than 150 NGOs participated. Union Law Minister Arjun Ram Meghwal was the chief guest of the program who inaugurated the 'Manthan 2023' programme. At the beginning of the program, Lt. Gen.(R.) Nitin Kohli, President of Seema Jagran Manch, Delhi Province, gave a welcome speech. He said that today the biggest challenges in the border areas are related to infiltration, drug trafficking and religious conversion. The reason behind this is the paucity of resources in the border areas and the non-fulfillment of the needs of the people there. Anti-national elements cheat the innocent people living in the border areas by luring money. We have to fight against such anti-national elements and stop them. Seema Jagran Manch is constantly engaged in working for the prevention of such activities. Seema Jagran Manch runs education centers in border areas, does health related activities like arranging many ambulances in these areas etc. Today there is a great need of public awareness so that the voice of the people of the border areas reaches the masses. Every section of the society needs to move forward to protect the interests of the border areas. When we work together then only India will have a secure border. After this, Law Minister Arjun Ram Meghwal addressed the people present in the programme. He said that Prime Minister Narendra Modi has far-reaching thinking about the border areas, he says that to strengthen the border areas, it is very important to have a strong infrastructure there. The law ministers said that the people who ruled after independence were responsible for the problems in Jammu and Kashmir. The governments of that time did not show interest in developing Jammu and Kashmir by calling it a hilly region, more attention was paid to the development of other states instead of Jammu and Kashmir. When Article 370 was in force in Jammu and Kashmir, during that time the people there felt themselves insecure because of the terrorists, but today after the removal of Article 370, the people of this border state feel safe. There is almost no terrorism there. It is a good initiative to organize 'Manthan 2023' by Seema Jagran Manch, which will help in solving the problems in the border areas in the society. The Law Minister said that the border areas are also naturally very beautiful whether it is Jammu Kashmir, Ladakh or the state of North East India. We should promote tourism in the border states. There are such wonderful places in many states whose beauty will mesmerize you. Seema Jagran Manch is doing a unique work related to this, for which the organization deserves praise. Seema Jagran Manch makes its workers travel to the border areas 2-3 times a year through Seema Darshan Yatra so that they can understand the situation there and promote tourism there. Other people of the society should contribute in promoting tourism in the border areas. Many different sessions were organized in the program, in which the points like migration from border areas, tourism in border areas, research on demographic change, threats and measures, infrastructure development, agricultural development and environmental challenges were discussed in depth, and a plan was made to work on it in a coordinated manner. Apart from this, representatives of several NGOs tried to establish mutual coordination by giving presentations in front of CSR heads of various public sector units through Manthan 2023 of Seema Jagran Manch. This initiative launched for the security of border areas through brainstorming of Seema Jagran Manch will definitely help in identifying the emerging challenges and get solutions in the challenges they face by implementing their action plan for the development of border area.

सीमा जागरण मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम

सीमा जागरण मंच ने 'मंथन' कार्यक्रम आयोजित किया

सीमा क्षेत्र का एकीकृत विकास कई एनजीओ की भूमिका

तेजस न्यूज संवाददाता

गाजियाबाद। राष्ट्रव्यापी स्तर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में लिए कार्य करने वाली गैर-सरकारी संगठन सीमा जागरण मंच ने रविवार को गाजियाबाद के कौशांबी स्थित रेडिशन ब्लू होटल में 'सीमा क्षेत्र का एकीकृत विकास - एनजीओ की भूमिका' विषय पर 'मंथन 2023' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें 150 से अधिक एनजीओ के प्रतिनिधियों समेत 300 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रहे जिन्होंने मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

कार्यक्रम की शुरुआत में सीमा जागरण मंच के दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली ने कहा कि आज सीमावर्ती क्षेत्रों में सबसे बड़ी चुनौती घुसपैठ, मादक पदार्थों की तस्करी और धर्मांतरण से जुड़ी हुई हैं। इसके पीछे कारण है सीमावर्ती क्षेत्रों में संसाधनों की कमी और वहां के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होना। देश विरोधी तत्व रुपयों का लालच देकर सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मासूम लोगों को धोखा देते हैं। हमें ऐसे ही देश विरोधी तत्वों के खिलाफ लड़ना है और उन्हें रोकना है। सीमा जागरण मंच निरंतर ऐसी गतिविधियों की रोकथाम के लिए कार्य करने में जुटा हुआ है। सीमा जागरण मंच सीमावर्ती क्षेत्रों में शिक्षा केन्द्रों को संचालित करता है, स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियां करता है जैसे उन क्षेत्रों में कई एंबुलेंस की व्यस्था करना इत्यादि। आज सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की आवाज जन-जन तक पहुंचे के लिए जन जागरण की अत्यधिक आवश्यकता है। समाज के हर वर्ग सीमावर्ती क्षेत्रों के हितों की रक्षा के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जब हम एक साथ काम करेंगे तभी तो होगा सुरक्षित सीमा समर्थ भारत।

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर दूरगामी सोच है, उनका कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना बेहद जरूरी है।

कार्यक्रम में कई अलग-अलग सत्र आयोजित किए गए जिसमें प्रमुख रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन, सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन, जनसांख्यिकीय बदलाव पर शोध, खतरों और उपायों, बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि विकास और पर्यावरणीय चुनौतियों जैसे बिंदुओं पर गहनता से चर्चा की गई और इस पर समन्वयक रूप से कार्य करने की योजना बनी।

इसके अलावा कई एनजीओ के प्रतिनिधियों ने सीमा जागरण मंच के मंथन 2023 के जरिए विभिन्न पब्लिक सेक्टर यूनिट के सीएसआर प्रमुखों के सामने प्रस्तुतिकरण देकर आपसी समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया।

सीमा जागरण मंच की मंथन के जरिए सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई यह पहल निश्चित रूप से उन चुनौतियों में उभरती चुनौतियों की पहचान करने और समाधान प्राप्त करने में मदद करेगी जो वे सीमा क्षेत्र के विकास के लिए अपनी कार्य योजना को क्रियान्वित कर रहे है।

सीमा जागरण मंच के कार्यक्रम में 'सीमा क्षेत्र का एकीकृत-विकास एनजीओ की भूमिका' पर हुआ मंथन 2023

मेघवाल ने कहा-सीमावर्ती क्षेत्र को लेकर पीएम मोदी की सोच दूरगामी

12 Jun 2023 - Page 4

---

370 हटने पर कश्मार सुरक्षित : मेघवाल

बॉर्डर वाले इलाकों में विकास को लेकर हुई संगोष्ठी 'मंथन'

■ **विस, नई दिल्ली :** राष्ट्रीय स्तर पर सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन सीमा जागरण मंच ने रविवार को एक संगोष्ठी 'मंथन 2023' का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 150 से ज्यादा एनजीओ के प्रतिनिधियों समेत 300 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सीमा जागरण मंच के दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली ने बॉर्डर एरिया में बढ़ती घुसपैठ, मादक पदार्थों की तस्करी और धर्मांतरण को लेकर अपनी बात रखी और संसाधनों की कमी को इसकी प्रमुख वजह बताई। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे देशविरोधी तत्वों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना है और उन्हें रोकना है। वहीं, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवला ने बॉर्डर एरिया में इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि सीमा जागरण मंच की ओर से ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना एक अच्छी पहल है। इससे बॉर्डर इलाकों की समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी।

आयोजन — सीमा जागरण मंच का 'मंथन 2023' कार्यक्रम आयोजित

सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर पीएम मोदी की सोच दूरगामी : अर्जुन मेघवाल

गाजियाबाद, 11 जून (देशबन्धु)। राष्ट्रव्यापी स्तर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में लिए कार्य करने वाली गैर-सरकारी संगठन सीमा जागरण मंच ने रविवार को गाजियाबाद के कौशांबी स्थित रेडिशन ब्लू होटल में 'सीमा क्षेत्र का एकीकृत विकास -एनजीओ की भूमिका' विषय पर 'मंथन 2023' कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें 150 से अधिक एनजीओ के प्रतिनिधियों समेत 300 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रहे जिन्होंने मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

कार्यक्रम की शुरूआत में सीमा जागरण मंच के दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने कहा कि आज सीमावर्ती क्षेत्रों में सबसे बड़ी चुनौती घुसपैठ, मादक पदार्थों की तस्करी और धर्मांतरण से जुड़ी हुई हैं। इसके पीछे कारण है सीमावर्ती क्षेत्रों में संसाधनों की कमी और वहां के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होना।

देश विरोधी तत्व रुपयों का लालच देकर सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मासूम लोगों को धोखा देते हैं। हमें ऐसे ही देश विरोधी तत्वों के खिलाफ लड़ना है और उन्हें रोकना है।

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर दूरगामी सोच है, उनका कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों

■ **कार्यक्रम में 150 से अधिक एनजीओ के प्रतिनिधियों समेत 300 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया**

को मजबूत करने के लिए वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना बेहद जरूरी है। कानून मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो समस्याएं थी उसकी देन स्वतंत्रता के पश्चात शासन करने वाले लोग थे। उस दौरान की सरकारों ने जम्मू कश्मीर को पहाड़ी क्षेत्र बताकर वहां का विकास करने में रुचि नहीं दिखाई, जम्मू कश्मीर की बजाय अन्य राज्यों के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया गया। जब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू था उस दौरान वहां के लोग खुद को आतंकियों के चलते खुद को असुरक्षित महसूस करते थे लेकिन आज अनुच्छेद 370 हटने के बाद इस सीमावर्ती राज्य के लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। वहां आतंकवाद न के बराबर है। सीमा जागरण मंच द्वारा मंथन कार्यक्रम का आयोजन करना एक अच्छी पहल है जिससे समाज में सीमावर्ती क्षेत्रों में जो समस्याएं है जो उसको दूर करने में सहायक होंगी।

कार्यक्रम में कई अलग-अलग सत्र आयोजित किए गए। कई एनजीओ के प्रतिनिधियों ने सीमा जागरण मंच के मंथन 2023 के जरिए विभिन्न पब्लिक सेक्टर यूनिट के सीएसआर प्रमुखों के सामने प्रस्तुतिकरण देकर आपसी समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया।

घुसपैठियों को रोकने के लिए एकजुट होना होगा : अर्जुन

माई सिटी रिपोर्टर

साहिबाबाद। सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठियों को रोकने और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को मिलकर काम करना होगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने यह बात कौशांबी स्थित एक होटल में आयोजित गैर सरकारी संगठन सीमा जागरण मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही।

सीमा क्षेत्र का एकीकृत विकास-एनजीओ की भूमिका विषय पर आयोजित कार्यक्रम में 150 से अधिक एनजीओ के प्रतिनिधि समेत 300 से अधिक लोग कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कानून मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र प्राकृतिक रूप से भी काफी सुंदर हैं, चाहे जम्मू-कश्मीर, लद्दाख हो या पूर्वोत्तर भारत के राज्य। हमें सीमावर्ती राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे यहां कि आर्थिक

कार्यक्रम का शुभारंभ करते केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल। संवाद

स्थिति मजबूत होगी। कार्यक्रम की शुरुआत में सीमा जागरण मंच के दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली ने संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि आज सीमावर्ती क्षेत्रों में सबसे बड़ी चुनौती घुसपैठ, मादक पदार्थों की तस्करी और धर्मांतरण से जुड़ी हुई हैं। इसके पीछे कारण है सीमावर्ती क्षेत्रों में संसाधनों की कमी है।

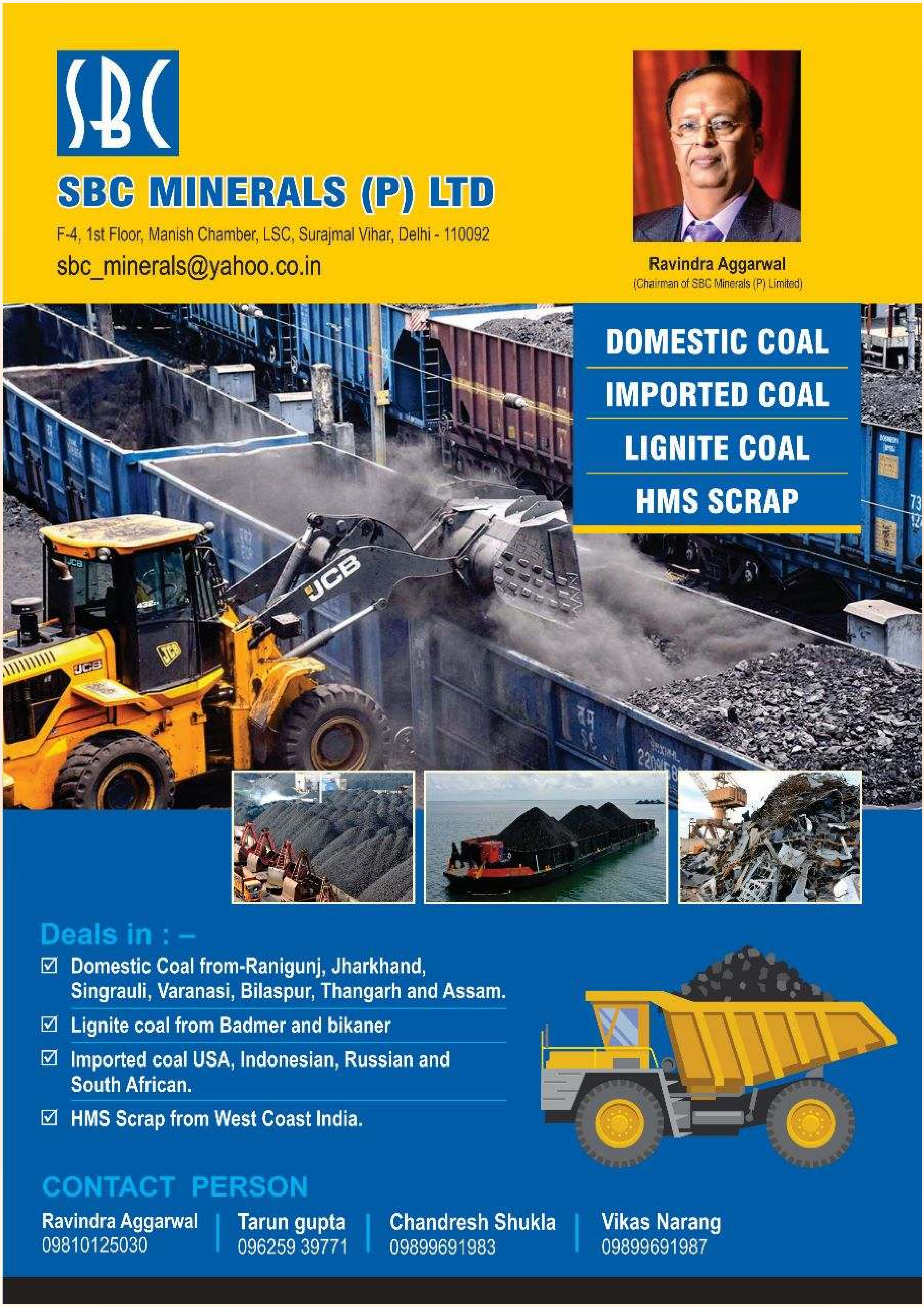
SBC
SBC MINERALS (P) LTD
F-4, 1st Floor, Manish Chamber, LSC, Surajmal Vihar, Delhi - 110092
sbc_minerals@yahoo.co.in
Ravindra Aggarwal
(Chairman of SBC Minerals (P) Limited)
DOMESTIC COAL
IMPORTED COAL
LIGNITE COAL
HMS SCRAP
JCB
Deals in : –
☑ Domestic Coal from-Ranigunj, Jharkhand, Singrauli, Varanasi, Bilaspur, Thangarh and Assam.
☑ Lignite coal from Badmer and bikaner
☑ Imported coal USA, Indonesian, Russian and South African.
☑ HMS Scrap from West Coast India.
CONTACT PERSON
Ravindra Aggarwal 09810125030
Tarun gupta 096259 39771
Chandresh Shukla 09899691983
Vikas Narang 09899691987